

RIN No.: MPBIL/2001/5256  
DAVP Code : 128101  
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023  
Publish Date : Every Month Dt. 05  
Posting Date : Every Month Dt. 15  
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष 22 अंक 11 05 जुलाई 2022

# जगत विज्ञान

## आग्निपथ पर मोदी की आग्निपरीक्षा सवालों के घेरे में अग्निपथ योजना





प्रेरणा स्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक  
कार्यकारी संपादक  
मध्यप्रदेश संवाददाता  
राजनीतिक संवाददाता  
विशेष संवाददाता  
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ  
छत्तीसगढ़ संवाददाता

पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ  
गोवा ब्यूरो चीफ  
गुजरात ब्यूरो चीफ  
दिल्ली ब्यूरो चीफ  
पटना संवाददाता  
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ  
बुंदेलखण्ड संवाददाता  
विधिक सलाहकार

विजया पाठक  
समता पाठक  
अर्चना शर्मा  
समीर शास्त्री  
बिन्देश्वरी पटेल  
मणिशंकर पाण्डेय  
आनन्द मोहन  
श्रीवास्तव,  
अमित राय  
अजय सिंह  
गौरव सेठी  
विजय वर्मा  
सौरभ कुमार  
वेद कुमार  
रफत खान  
एडवोकेट  
राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

**भोपाल**

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

**छत्तीसगढ़**

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

**स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,**

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज

एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लॉट नं. 28 सुरभि विहार

बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17,

शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया

पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय

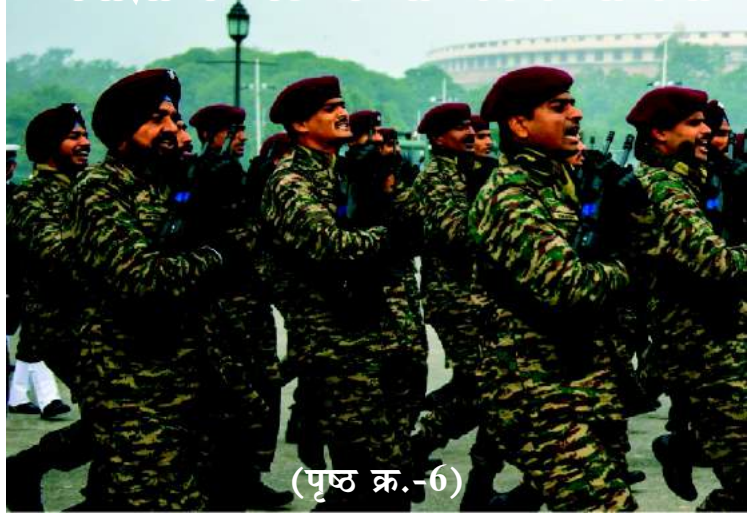
रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख

एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

**E-mail : jagat.vision@gmail.com**

**Website: www.jagatvision.in**

# अग्निपथ पर मोदी की अग्निपरीक्षा सवालोंने के घेरे में अग्निपथ योजना



(पृष्ठ क्र.-6)

- यूनिवर्सिटियों के चांसलर को लेकर फिर मुख्यमंत्री.....22
- जम्मू कश्मीर : दर्द की दास्तान सुनने वाला कौन .....25
- महाराष्ट्र की राजनीति के नये किंग मेकर बने एकनाथ शिंदे .....30
- राहुल गांधी पर ईडी का एक्शन और छत्तीसगढ़ .....33
- नीर के लिए पीर का स्थाई समाधान है जल जीवन मिशन .....36
- फिर लौटेगा गौ-सदनों का वैभव .....40
- अब ईडी के निशाने पर गांधी परिवार ..... 42
- रबर स्टॉप बनकर न रहे राष्ट्रपति का पद .....49
- नूपुर शर्मा: बयान से बर्खास्तगी तक .....52
- क्या फिर एराने लगा कोरोना .....54
- न्यायालयों में राजस्व मामलों का बोझ .....56
- अधिक कार्बन उत्सर्जन पर कड़ाई जरूरी .....60
- Public Relations in Banking Sector .....63







## 2023 की बिस्मात बिछायेंगे निकाय चुनाव परिणाम

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव चरम पर हैं। पहले चरण के चुनाव सम्पन्न भी हो चुके हैं। पहले चरण के चुनाव परिणामों ने प्रदेश की सत्तासीन बीजेपी सरकार को कुछ सकते में डाल दिया है। इन चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को शिकस्त दी है। परिणामों का आंकलन करने पर पता चला है कि कांग्रेस ने भाजपा के कई मजबूत गढ़ों को ढहा दिया है। इनमें वे जिले भी शामिल हैं, जिन्हें परंपरागत रूप से भाजपा के लिए बेहद मजबूत माना जाता है।

चुनाव परिणामों से लगने लगा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मिशन 2023 का जो बिगुल फूँका है उसमें वे सफल होते दिखाई दे रहे हैं। इस जीत से निश्चित ही उन्हें आगे की राह आसान लगेगी। देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में जबरदस्त मेहनत करते दिखाई दे रही हैं। सभी के इरादे साफ है कि उन्हें मिशन 2023 को वापस से सफल बनाना है। कांग्रेस का दावा है कि वो 75 फीसदी सीटें इस चुनाव में जीतेगी। अगर कांग्रेस अपने इस फैसले पर कायम रही तो निश्चित ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार होगी और इस हार से उबरने के लिए भाजपा को 10 साले से यादा का समय लग जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के पहले कांग्रेस में गुटबाजी की खूब चर्चाएं हो रही थी। लोगों को लगने लगा था कि शायद एक बार फिर कांग्रेस आपसी गुटबाजी में उलझ चुकी है लेकिन समय को भांपते हुए कांग्रेस को इससे बाहर निकालने के लिए कमलनाथ खुद कमान संभाली। उन्होंने प्रदेश के सभी दिग्गजों को एकजुट करने का प्रयास किया। साथ ही जिम्मेदारियां देकर सबको मिशन में लगने को कहा। जिसका नतीजा यह हुआ कि आज सभी कांग्रेसी एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में हैं और मेहनत कर रहे हैं।

देखा जाए तो प्रदेश भाजपा के नेता दोबारा सत्ता में लौटने के बाद से ही जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है। उन्हें हर बार ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो जोड़ तोड़ करके दोबारा से फिर सत्ता में बनाने में कामयाब हो जायेंगे। यही वजह है कि भाजपा के बड़े नेता जमीन पर काम करने के बजाय वल्लभ भवन के एसी रूम में बैठकर समय काट रहे हैं और शासकीय सुविधाओं का उपभोग करने में जुटे हुए हैं।

सूत्रों की माने तो बीजेपी की हालात की वजह है भाजपा की गुटबाजी और जिले में विधायकों की अपनी जिद रही है। विधायकों ने अपनी जिद और पसंद न पसंद के चलते जनाधारविहीन कार्यकर्ताओं को अधिक तबज्जो दी, जिसके चलते पहले चरण के मतदान में विपरीत रुझान सामने आए हैं। दूसरी वजह है भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की घोषणा के बाद भी पंचायत चुनाव में भाजपा ने नेता पुत्रों और रिश्तेदारों को टिकट बांटने की परंपरा को जारी रखा। बावजूद उसके नेता पुत्र और रिश्तेदारों को पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त मिली।

दरअसल नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव परिणामों से प्रदेश में भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय होगी। यह चुनाव 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी साबित होगा। इन चुनावों के परिणाम राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी का भविष्य तय करेंगे। साथ ही तय कर देंगे कि विधानसभा चुनाव में कौन-कौन से मुद्दे हावी हो सकते हैं। वैसे निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और इसमें सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे हावी रहते हैं, पर इस बार दिलचस्प यह है कि चुनाव से स्थानीय मुद्दे गायब हैं। भाजपा अपने विकास को जनता के सामने रख वोट मांग रही है। कांग्रेस सरकार की नाकामियों को बताकर वोटों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। शिवराज सिंह ने लगभग सभी बड़े शहरों में मेयर प्रत्याशियों के खुद जाकर नामांकन भरवाए और प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो और लगातार सभाएं भी कर रहे हैं।

विजया पाठक



# अग्निपथ पर मोदी की अग्निपरीक्षा

## सवालों के घेरे में अग्निपथ योजना



“ मोदी सरकार देश को बेरोजगारी की आग में जलाकर अग्निपथ नाम का मरहम लगाने के लिए अग्निपथ योजना का आइना दिखा कर युवाओं को ठगने का काम कर रही है। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद पूरे देश के अंदर जो वातावरण बना है उसके लिए पूर्ण रूप से मोदी सरकार दोषी है। मोदी सरकार आज देश की बर्बादी का मंजर देख रही है। लाखों लाख पद विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े हैं उसको भरने की दिशा में कोई घोषणा नहीं हो रही है। फौज के अंदर भी लाखों लाख पद खाली हैं उस पर सरकार की नजर नहीं है। सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 02 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। वह तो नहीं मिली और अग्निपथ योजना का आइना दिखा कर युवाओं को ठगने का काम और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। सरकार नौकरी के नाम पर आंदोलित करने के लिए युवाओं को मजबूर कर रही है। योजना को जल्दबाजी में पेश किया गया है। सशस्त्र बलों में शामिल होना कोई अन्य नौकरी पाने जैसा नहीं है। यह दिल और गर्व की बात है। कौन सेना में शामिल होता है? न तो राजनेताओं, न नौकरशाहों और न ही व्यापारियों के बच्चे सेना में शामिल होते हैं। ज्यादातर गरीब ग्रामीणों और किसानों के बच्चे सशस्त्र बलों में आते हैं, क्योंकि वे भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। वे वर्षों मेहनत कर इसके लिए तैयारी करते हैं। कार्यकाल घटाकर मात्र चार वर्ष करने से उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। चार साल बाद अग्निवीरों को अधर में छोड़ दिया जाएगा। सेना में 1.10 लाख से अधिक रिक्तियों का बैकलॉग भी नहीं भरा गया है। युवाओं में असुरक्षा भाव व्याप्त है और वे यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें देश की सेवा करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। योजना के ऐलान के बाद से ही इसको लेकर देशभर में बवाल मचा है। कई राज्यों में आगजनी, पत्थरबाज़ी की घटनाएं घटीं। बिहार और उत्तर प्रदेश में तो इसका विरोध चरम पर है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि विदेशों में भी सेना में इस तरह की भर्तियां होती रही हैं लेकिन ये नहीं बताती कि जहां पर भी ये लागू है वहां सेना में सेवा देना सभी के लिए अनिवार्य है। वहां पर इसके लिए कानून है, लेकिन अग्निपथ योजना में ऐसा नहीं है। योजना को लेकर कार्पोरेट सेक्टर के लोग भी तरह-तरह के प्रलोभन लेकर योजना को बेहतर बता रहे हैं। कोई आरक्षण की बात कर रहा है तो कोई रियायतों की बात कर रहा है। ”

### विजया पाठक

सेना में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से मोदी सरकार अग्निपथ योजना लेकर आयी है। यह योजना युवाओं से जुड़ी है। क्योंकि

योजना के तहत देश के युवाओं को सेना में कुछ समय के लिए भर्ती किया जायेगा। कम अवधि के लिए होने वाली भर्ती को लेकर ही सारे देश में बवाल मचा है।

सरकार ने इस योजना को बड़े ही चालाकी से बनाई है। जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही साथ ही सेना की गरिमा पर भी प्रश्नचिह्न लगने का अंदेश





है। सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देख रहे लाखों युवाओं को केंद्र सरकार ने सेना में शामिल होने एक मौका देने का प्रयास तो किया लेकिन सरकार का यह प्रयास सार्थक होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कारण है अग्निपथ योजना में युवाओं को सुरक्षित भविष्य का अभाव दिखना। यही कारण है कि इस योजना की घोषणा के बाद से ही पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। युवा आशुित हैं। सरकार भले ही तमाम तर्क देकर युवाओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश कर रही है लेकिन बेरोजगार युवाओं का सरकार की मंशा पर तीखे प्रहार कर दिये हैं। सरकार तर्क दे रही है कि इस भर्ती के बाद रिटायरमेंट के बाद इन्हें और अन्य भर्तियों में लाभ देने जैसे कई और अन्य

**केन्द्र सरकार द्वारा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए लाई गई अग्निवीर योजना के वर्तमान स्वरूप का विरोध हो रहा है। इस योजना में भर्ती युवा का 04 वर्ष अपने भविष्य की अनिश्चितता की चिंता में ही बीत जावेगा। इस योजना से वे युवा जिन्होंने पुरानी योजना की तैयारी की थी और परीक्षाओं में भाग लिया था छला महसूस कर रहे हैं।**

सुविधाएं दी जायेगी। लेकिन देश के युवाओं को यह बात रास नहीं आ रही है।

केन्द्र सरकार द्वारा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए लाई गई अग्निवीर योजना के वर्तमान स्वरूप का

विरोध हो रहा है। इस योजना में भर्ती युवा का 04 वर्ष अपने भविष्य की अनिश्चितता की चिंता में ही बीत जावेगा। इस योजना से वे युवा जिन्होंने पुरानी योजना की तैयारी की थी और परीक्षाओं में भाग लिया था छला महसूस कर रहे हैं। केन्द्र सरकार हठधर्मिता से योजना थोपती है। जैसे ही सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च की। कई शहरों में प्रदर्शन और विरोध की चिंगारी धधक उठी। सेना में भर्ती होने का सपना संजोये कई राज्यों के नौजवान सड़क पर उतर आए। उत्तरप्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। बिहार के लखीसराय, छपरा, समस्तीपुर, आरा समेत कई जिलों में ट्रेनें फूंक दी गईं। राजस्थान के अनेक हिस्सों में भी युवाओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के



# क्या है अग्निपथ योजना ?

भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत हर साल 45 हजार युवाओं को इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होकर सेवा करने का मौका मिलता है। 17.5 साल से लेकर 21 साल के युवाओं को 4 साल तक के लिए देश की रक्षा करने का अवसर मिलेगा। हालांकि शुरू हुए बवाल के बाद रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ इस साल की अग्निवीरों की भर्ती की उम्र 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है।

अग्निपथ योजना का प्रारंभिक लक्ष्य 46,000 अग्निवीरों को नियुक्त करना है, जिनमें से 34,000 चार वर्ष पश्चात 11 लाख रुपये के एकमुश्त सेवानिधि लाभ के साथ सेवामुक्त हो जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य पांचवें वर्ष तक 90 हजार, 2030 तक 1,27,000 और अंत सेना में नियमित सैनिकों और अग्निवीरों के अनुपात को 50-50 प्रतिशत करना है। ऐसा होने से सेना की औसत आयु 32 वर्ष से घटकर 26 हो जाएगी। अभी भारतीय सेना में केवल 2,50,000 सैनिकों की आयु 25 वर्ष से कम है। भर्ती की न्यूनतम आयु साढ़े 17 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास है। अग्निपथ दरअसल देशव्यापी शॉर्ट-टर्म यूथ रिक्रूटमेंट स्कीम है। पहली भर्ती प्रिया में युवाओं को छह महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह अवधि सेवा के कुल चार साल में शामिल होगी। हर अग्निवीर को भर्ती के पहले साल 30 हजार रू. महीना तनखाह मिलेगी। इसमें से 21 हजार रू. उसे वेतन के रूप में मिलेंगे और बाकी 09 हजार रू. अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होंगे। फंड कांट्रीब्यूटरी होगा, जिसमें इतनी राशि सरकार भी डालेगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनखाह बढ़कर 33 हजार, तीसरे साल 36.5 हजार तो चौथे साल 40 हजार रुपये हो जाएगी। फंड की राशि तथा ब्याज के रूप में जमा 11.71 लाख रू. उसे नौकरी से बाहर होते समय मिलेंगे। साथ ही सेवा के दौरान शहीद होने या दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद का मिलेगी। शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत एक करोड़ से यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। साथ ही शेष सेवा अवधि का वेतन भी दिया जाएगा। कुल अग्निवीरों में से एक चौथाई को अच्छे रिकार्ड के आधार पर सेना में पक्की नौकरी दी जाएगी। 14 लाख से अधिक सक्रिय कर्मियों की ताकत के साथ यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल है। अन्य कई स्वतंत्र और आनुषांगिक इकाइयाँ जैसे- भारतीय सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल, राष्ट्रीय राइफल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इत्यादि। यह दुनिया के सबसे बड़ी और प्रमुख सेनाओं में से एक है। संख्या की दृष्टि से भारतीय थलसेना के जवानों की संख्या दुनिया में चीन के बाद सबसे अधिक है। जबसे भारतीय सेना का गठन हुआ है, भारत ने दोनों विश्वयुद्ध में भाग लिया है। भारत की आजादी के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन युद्ध 1948, 1965 तथा 1971 में लड़े हैं जबकि एक बार चीन से 1962 में भी युद्ध हुआ है। इसके अलावा 1999 में एक युद्ध कारगिल युद्ध पाकिस्तान के साथ दुबारा लड़ा गया। भारतीय सेना परमाणु लैपटॉप, उन्नत तकनीक परमाणु हथियार से लैस है और उनके पास उचित ट्रायड मिसाइल अस्त्र-शस्त्र भी उपलब्ध हैं। वर्तमान में सेना में एक सैनिक की पक्की नौकरी भी साढ़े 17 साल की होती है। लेकिन उसे आजीवन पेंशन और साथ ही तमाम दूसरी सुविधाएं भी मिलती रहती हैं। जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, ये ज्यादातर वो राज्य हैं, जहां सेना में सबसे ज्यादा भर्ती होती है, जहां रोजगार के दूसरे अवसर बहुत कम हैं और जहां सेना की नौकरी देश सेवा के साथ पक्की नौकरी की गारंटी भी है, जो एक मानसिक निश्चिंतता और सामाजिक प्रतिष्ठा भी देती है। ऐसे राज्यों के युवाओं का एकमात्र सवाल यही है कि चार साल बाद क्या ?

खिलाफ नारेबाजी की। मध्यप्रदेश में अग्निपथ योजना के खिलाफ

प्रदर्शनकारियों ने ग्वालियर और इंदौर में विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के

पिथौरागढ़ में कई युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन





बड़ा सवाल यह है कि जो अग्निवीर भर्ती होंगे वो चार साल बाद क्या करेंगे? कहां जाएंगे? उन्हें चार साल बाद नौकरी कहां मिलेगी? सरकार को किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ बंद करना चाहिए। इस योजना से प्रतिवर्ष हजारों युवा अनिश्चितता के साथ डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। अग्निवीर योजना किसी के सामने भोजन की थाली रखकर वापस थाली खींच लेने जैसी है। फिर भूखा युवा क्या करेगा, कुछ युवा गलत मार्ग पर चल पड़े तो देश में अराजकता की स्थिति हो सकती है, इस पर केंद्र सरकार को संवेदना, जागरूकता से विचार करना चाहिए।

किया। झारखंड में अग्निपथ योजना के खिलाफ सेना में भर्ती के आकांक्षी सैकड़ों अभ्यर्थियों ने रांची स्थित सेना भर्ती कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। विरोध की आग तेलंगाना तक भी पहुंची। योजना के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपे गए। जिस तरह से प्रदर्शन का दायरा बढ़ रहा है, उससे साफ हो चला है कि सरकार ने बड़ी गलती कर दी है? सोशल मीडिया पर लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार ने 04 साल के लिए भर्ती और आकर्षक इनीमेंट बताकर इस योजना को शुरू किया था लेकिन

## युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती योजना

अग्निवीर बनने वाले युवाओं को ये रास नहीं आई। उन्होंने सवाल किया कि चार साल की अस्थायी नौकरी करने के बाद वे क्या करेंगे? वरीयता देने का सरकार का ऑफर युवाओं को समझ में नहीं आया। उनका कहना है कि अगर इतनी नौकरियां होतीं तो आज इतनी बेरोजगारी ही क्यों होती। विपक्ष सरकार पर उंगली उठा रहा है। लगभग सभी विपक्षी दलों ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग करनी शुरू कर दी है। सड़कों पर भले ही युवा दिख रहे हों, पर उनके घरवाले, आस-पड़ोस और आम लोग भी सरकार की इस

योजना से नाराज हैं। ऐसे में यह बातें भी होने लगी हैं कि क्या मोदी सरकार ने 08 साल के भीतर तीसरी बड़ी गलती कर दी है?

तो युवा निश्चित होकर कैसे देशसेवा कर सकेगा। अग्निवीर योजना ऐसी हो कि युवा चार वर्षों पश्चात किसी राजनैतिक पार्टी का नहीं अपितु जीवन भर देश का

जावेगा तो तीनों सेनाओं में कुल 11,000 की प्रतिवर्ष भर्ती होगी जबकि हजारों सैनिक प्रतिवर्ष रिटायर्ड हो रहे हैं। यह भी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और युवाओं के

## बड़ा सवाल: किस पथ पर चलेंगे देश के नौजवान?

केन्द्र सरकार को युवाओं की देशभक्ति को रुपये पैसों से नहीं तौलना चाहिए। युवा देशभक्ति के साथ अपने व परिवार के सुरक्षित भविष्य की भावना से सेना में जाता है। इसमें से एक हिस्सा हटा दिया जाता है

चौकीदार बने। सेना में पिछले दो वर्षों से भर्ती प्रक्रिया बाधित है और सरकार ने केवल 46,000 अग्निवीर की भर्ती तीनों सेनाओं की मिलाकर करने की योजना लाई है उसमें से भी 35,000 को निकाल दिया

साथ धोखा है। सरकार अग्निवीर योजना में सुधार कर ज्यादा युवाओं को देशसेवा का मौका दें।

वर्तमान समय में भारत सरकार ने तीनों सेवाओं (सेना, नौसेना और वायुसेना) में





## अग्निवीर योजना से युवाओं को नुकसान

- ▶▶ अग्निपथ योजना उम्मीदवारों को केवल 04 साल के लिए रोजगार प्रदान करेगी।
- ▶▶ केवल 25 प्रतिशत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के बाद स्थायी किया जाएगा और अन्य 75 प्रतिशत को नौकरी छोड़नी होगी।
- ▶▶ अग्निपथ योजना 2022 के दौरान नियुक्त उम्मीदवार को कोई पेंशन नहीं मिलेगी।
- ▶▶ सरकारी सेवा निधि योजना से 04 वर्ष बाद एकमुश्त राशि में से केवल 11 लाख ही अग्निवीरों को मिलेंगे जबकि 11 लाख में से कुछ राशि मासिक आधार पर भर्ती के वेतन से काट ली जाएगी।
- ▶▶ चयनित उम्मीदवारों को केवल गैर-कमीशन रैंक जैसे सिपाही, नाइक और लांस नायक के लिए भर्ती किया जाएगा।
- ▶▶ यह भर्ती सिर्फ 17.5 से 23 साल के उम्मीदवारों के लिए है।
- ▶▶ नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है क्योंकि 04 साल की सेवा के बाद उम्मीदवार फिर से बेरोजगार हो जाएंगे।
- ▶▶ अन्य सरकारी नौकरियों की तरह उम्मीदवार को कोई अतिरिक्त या बुनियादी लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- ▶▶ इस अग्निवीर योजना में चार साल के सेवाकाल का मतलब होगा कि उसके बाद अन्य नौकरियां उनकी पहुंच से बाहर होंगी और चार साल की अवधि पूरा करने वाले सैनिक पुनः सेवा के लिये पात्र नहीं होंगे।
- ▶▶ अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों को कोई पेंशन लाभ प्राप्त नहीं होगा, अतः ऐसी स्थिति में अधिकांश के लिये अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण करने हेतु दूसरी नौकरी की तलाश करना ज़रूरी होगा।
- ▶▶ भारत की सेना चार साल के अनुभवी सैनिकों को बाहर कर देगी जिससे सेना अनुभवी सैनिकों का अभाव महसूस करेगी।
- ▶▶ थल सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होने वाले जवानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा लेकिन इनमें पुरुष और महिलाओं को चार साल बाद सेवा से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे स्थिति पुनः शून्य पर आ जाएगी।

सैनिकों की भर्ती के लिये अग्निपथ योजना का प्रस्ताव शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत देशभक्त और देशभक्ति की कामना रखने वाले प्रेरित युवाओं को चार साल की

अवधि के लिये सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति दी जाती है। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इस नई योजना के

तहत लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी और अधिकांश केवल चार वर्षों में सेवा छोड़ देंगे। चार साल के बाद बैच के केवल





25प्रतिशत को ही 15 साल की अवधि के लिये उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा जारी इस अग्निवीर योजना को देशभक्त और प्रेरित युवाओं के साथ सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इस अग्निवीर योजना के तहत यह परिकल्पना की गई है कि सशस्त्र बलों में वर्तमान में औसत आयु 32 वर्ष है जो 6-7 वर्ष घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। अभी भारत में 14 लाख सैनिक हैं। देश में ऐसे लाखों युवा हैं, जो नियमित सैन्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सशस्त्रबलों में शामिल होने से चूक जाते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश भारतीय

**इस अग्निवीर योजना के तहत यह परिकल्पना की गई है कि सशस्त्र बलों में वर्तमान में औसत आयु 32 वर्ष है जो 6-7 वर्ष घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। अभी भारत में 14 लाख सैनिक हैं। देश में ऐसे लाखों युवा हैं, जो नियमित सैन्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सशस्त्रबलों में शामिल होने से चूक जाते हैं।**

सैनिक, भर्ती के बाद लगभग 15 वर्ष की सेवा करते हैं और फिर लगभग 30-50 वर्षों के लिए पेंशन प्राप्त करते हैं। वर्ष 2013-14 में वेतन-पेंशन पर खर्च कुल रक्षा बजट का 42.2 प्रतिशत था, जोकि अब बढ़कर 48.4 प्रतिशत हो गया है। वन रैंक वन पेंशन योजना के बाद पेंशन पर रक्षा खर्च अन्य सैन्य व्ययों से कहीं अधिक हो गया है। सरकार द्वारा अग्निवीर योजना को देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।

पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं इसकी जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र



# खड़े हैं कई सारे सवाल?

क्या भरी जवानी में युवा सड़क पर होंगे? जो सेना या दूसरे सशस्त्र बलों में नहीं जा सकेंगे, वो क्या करेंगे? खतरा यह भी है कि कुछ सैन्य प्रशिक्षित युवा गलत रास्तों पर भी जा सकते हैं। चार साल की सेवा के दौरान जिनकी शादियां वगैरह हो जाएंगी, उनका पारिवारिक दायित्व भी बढ़ जाएगा। जिंदगी उन्हें नए सिरे से शुरू करनी होगी। अगर यही होना है तो वो अग्निवीर क्यों बनें? हालांकि सरकार की यह योजना कोई अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं है। आंदोलनकारी युवाओं का कहना है कि अग्निपथ योजना की सेवा शर्तें उनके रोजगार के अधिकार का हनन है। भारतीय संविधान में काम का अधिकार किसी भी



नागरिक का मौलिक अधिकार है। सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा पास करने के लिए युवा कोचिंग लेते हैं। पिछले दिनों रेलवे भर्ती में कथित धांधली के विरोध में उभरे युवा विरोध पर उतर आये थे। हर प्रतियोगी परीक्षा और उसके ताने-बाने से उनके अपने आर्थिक हित जुड़े होते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि युवाओं की आवाज को खारिज कर दिया जाए। उनका विरोध और मांग जायज हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि अग्निवीरों के साथ खुद सेना के भीतर किस तरह का व्यवहार होगा? क्या वो दोयम दर्जे के सैनिक होंगे या उन्हें पूर्णकालिक सैनिक के समान जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे? सेना खुद उन पर कितना भरोसा करेगी? गोपनीय

मोदी को लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ने ही युवाओं को सेना में भर्ती किए जाने का यह मजाक किया है। बड़ा सवाल यह है कि जो अग्निवीर भर्ती होंगे वो चार साल बाद क्या करेंगे? कहां जाएंगे? उन्हें चार साल बाद

नौकरी कहां मिलेगी? सरकार को किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ बंद करना चाहिए। इस योजना से प्रतिवर्ष हजारों युवा अनिश्चितता के साथ डिप्रेशन के शिकार हो जावेंगे। अग्निवीर योजना

किसी के सामने भोजन की थाली रखकर वापस थाली खींच लेने जैसी है। फिर भूखा युवा क्या करेगा, कुछ युवा गलत मार्ग पर चल पड़े तो देश में अराजकता की स्थिति हो सकती है, इस पर केंद्र सरकार को



अभियानों में उन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं? अग्निवीर इतनी कम अवधि में स्वयं को सेना के चरित्र में कितना ढल पाएगा? या उसकी स्थिति होमगार्ड जैसी ही रहेगी? इनके जवाब अभी मिलने हैं।

वैसे योजना के पक्षधरों का कहना है कि आज वैश्विक और भारत की भू-राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए पहली ज़रूरत भारतीय सेना को युवा बनाने की है। अब बड़ी संख्या के बजाए छोटी मगर कार्यक्षमता और तकनीकी रूप से दक्ष सेना की आवश्यकता ज्यादा है। अग्निवीर उसी दिशा में बड़ा और सामयिक कदम है। भविष्य में जो सेना की अपेक्षा के अनुरूप नहीं होंगे, उन्हें

बाहर का रास्ता दिखाना अब ज्यादा आसान होगा, क्योंकि सेना देश सेवा का माध्यम है न कि पक्की नौकरी की गारंटी। अब लड़ाइयां आमने-सामने की जगह टैक्नोलाजी से ज्यादा लड़ी जा रही हैं। भारतीय सेना को उसी के अनुरूप बनाना है। हालांकि इस पूरी योजना को लेकर सेना में भी दो तरह की राय हैं। एक वर्ग इसे भारतीय सेना की कार्यशैली और क्षमता में ज़रूरी सामयिक बदलाव का प्रतीक मानता है तो दूसरा इसे सेना के मूलभूत चरित्र और तानेबाने से खतरनाक छेड़छाड़ के रूप में देखता है, जिसके नतीजे विपरीत भी आ सकते हैं। विपक्ष ने मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि खर्चों में कटौती के लिए सेना ही निशाने पर क्यों? सवाल कई हैं। लेकिन फिलहाल तो अग्निपथ योजना का पथ शुरू में ही सुलगता दिख रहा है। यह योजना भारतीय सेना को कितना सक्षम बनाएगी यह तो चार साल बाद ही पता चलेगा।

बहरहाल योजना की खामियों पर बात हो सकती है, लेकिन उसके उग्र विरोध का कोई औचित्य नहीं दिखता। कृषि कानूनों की तरह सरकार के लिए सबक यह है कि ऐसी कोई भी महत्वाकांक्षी योजना लागू करने के पहले उस पर व्यापक जनमत बनाना और संदेहों को समय रहते दूर करना ज़रूरी है। उम्मीद की जाए कि इस योजना का हथकड़ी कृषि कानूनों की तरह नहीं होगा। सेना और सरकार जहां इस योजना का लाभ गिना रही है वहीं कई विशेषज्ञ इस योजना के दूरगामी परिणाम की आशंका जता रहे हैं। सेना में प्रशिक्षित युवाओं को चार साल बाद घर बैठा देने से उनके भटकने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

संवेदना, जागरूकता से विचार करना चाहिए।

**विपक्ष भी हुआ हमलावर-** अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, हमलावर होना लाजमी भी है

क्योंकि यह देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। मोदी सरकार को इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। मोदी सरकार को इस योजना की शर्तों और इसके लाभ पर पुनः

विचार करने की आवश्यकता है जिससे पूरे देश में फेल रही यह आगजनी की घटनाएं बंद हो सकें। योजना को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, केसी वेणुगोपाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विरोध जताया है।



 गृहमंत्री कार्यालय, HMO India  
@HMOIndia

'अग्निपथ योजना' युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए @narendramodi जी का एक दूरदर्शी व स्वागत योग्य निर्णय है।

इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

#BharatKeAgniveer

Translate Tweet

8:04 AM · 15/06/22 · Twitter for iPhone

CM Office, GoUP Retweeted

 Yogi Adityanath  
@myogiadityanath


माँ भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को @UPGovt प्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी।

युवाओं के उन्नयन एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित व पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

जय हिंद!

Translate Tweet

7:06 AM · 15/06/22 · Twitter Web App

 Varun Gandhi  
@varungandhi80

अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को यह 'सहूलियत' क्यों?

राष्ट्रक्षकों को पेन्शन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेन्शन छोड़ने को तैयार हूँ।

क्या हम विधायक/सांसद अपनी पेन्शन छोड़ यह नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले?

Translate Tweet

केंद्र सरकार की इस नई योजना की सेना में रहे कई पूर्व अधिकारियों ने भी

आलोचना की है और गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तर्क दिया चार साल की नौकरी

से देशभक्ति की भावना पर भी असर पड़ेगा। ऐसे युवा देश के लिए ज्यादा





जोखिम लेने से बचेंगे और किसी तरह चार साल की सेवा पूरी करनी चाहेंगे। मेजर जनरल बीएस धनोआ (सेवानिवृत्त) ने ट्वीट किया, सशस्त्र बलों के लिए हाल ही

में घोषित भर्ती नीति के लिए दो सिफारिशें हैं। पहला कि सेवा अवधि को सात साल तक बढ़ाया जाए और दूसरा कि जो लोग सेवा जारी रखने के इच्छुक हैं उनका कोटा

कम से कम 50 प्रतिशत किया जाए।

दरअसल, गांव हो या शहर लोगों में आम धारणा यही है कि सरकारी नौकरी मिलने का मतलब करियर सुरक्षित होता

## कार्पोरेट सेक्टर नहीं है सेना

अग्निपथ योजना को मोदी सरकार एक कार्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर लेकर आयी है। जिसमें बकायदा इसके फायदे बताए जा रहे हैं। इसकी खासियतों को बताया जा रहा है। जबकि हम जानते हैं कि सेना शौर्य, जुनून और जबे की सेवा है। इसमें न आर्थिक पक्ष को देखा जाता है और न ही खासियतों और खामियों को देखा जाता है। लेकिन इसे देश की बिड़बना ही कहा जा सकता है कि योजना की घोषणा के बाद तीन दिनों तक सरकार के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता और सेनाओं के शीर्ष अधिकारी योजना के विषय में एक सेल्समैन की तरह खासियतों को बताते रहे। संवाद और मशबरा करते रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सरकार ने योजना को लेकर एक सेल्स टीम का गठन किया है जो प्रोडक्ट को बेचने में तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इससे पहले देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।



## अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

**भारतीय वायु सेना, थल सेना, जल सेना की भर्ती की तैयारियों में जुटे युवाओं ने सरकार द्वारा लाभू की गई अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। युवाओं ने सरकार से इस योजना को वापस करके पूर्व में लाभू तीनों सेनाओं की भर्ती नियमावली के तहत नौकरी देने का मार्ग प्रशस्त किए जाने की मांग की। क्या कहना है युवाओं का.....**

**खिलवाड़ बंद करे सरकार-** केंद्र सरकार चार वर्ष सेना में नौकरी देकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार को पूर्व की तरह नौकरियां देने का इंतजाम करना चाहिए।

**-कौशलेंद्र यादव, विदोखर**

**वादे से मुकर रही है केंद्र सरकार-** केंद्र सरकार ने चुनाव पूर्व वादा किया था कि वह युवाओं को स्थाई रूप से नौकरी प्रदान करेंगे। लेकिन बाद में अग्निवीर योजना लाकर अपने वादे से मुकर रहे हैं।

**-रोहित सोनी, सुमेरपुर**

**देशहित में नहीं है अग्निवीर योजना-** आजाद भारत में कभी भी सेना में संविदा पर नौकरी देने का प्रावधान नहीं किया गया है। मौजूदा सरकार का यह कदम देश हित में नहीं है। चार साल बाद नौकरी से बाहर होने पर सेना की गोपनीयता भंग होने की संभावना बढ़ सकती है।

**-प्रवीण पाल, धरमपुर**

**पुरानी व्यवस्था के तहत हो फौज में भर्ती-** सरकार को तीनों सेनाओं में पूर्व की व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। पूर्व व्यवस्था से नौकरी पाने वाले युवा देश की रक्षा के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे। इस योजना से युवाओं के अंदर देश रक्षा की भावना नहीं जागृति हो सकती।

**-दीपक पाल, बसंत नगर**

है। लोग 18-20 घंटे तैयारी कर कड़ी प्रतिस्पर्धा के जरिए नौकरी में सिलेक्ट होते हैं। अगर वो सपना टूटता दिखाई दे रहा है तो लोग तैयारी छोड़कर गुस्सा दिखाने सड़क और रेलवे स्टेशनों पर आ गए हैं। इनके हाथ में तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद टीवी पर आकर यह कहना पड़ा था कि शायद मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। अब आंदोलनकारी युवा इस फैसले को बिना सोच-विचारकर उठाया गया कदम बता रहे हैं। वैसे तो 2014 के बाद से भाजपा ने मोदी सरकार को कुशल नेतृत्व, दृढ़निश्चय और मजबूत फैसले लेने वाली सरकार के तौर पर प्रचारित किया था। 370 खत्म करने का फैसला रहा हो या सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा कदम, देशवासियों में यही संदेश गया कि देशहित में जो भी फैसला सही होगा। मोदी सरकार उस पर आगे बढ़ने से हिचकिचाएंगी नहीं। सरकार ने भी साफ संदेश दिया कि वह किसी के दबाव में नहीं आएंगी। लेकिन कुछ फैसलों ने उसकी इस इमेज को धक्का पहुंचाया है।

**जहां से भर्ती ज्यादा, वहां बवाल ज्यादा**

ताजा विवाद अग्निपथ योजना को लेकर है। जिन राज्यों से सेना में बड़ी संख्या में लोग भर्ती होते हैं, वहां विरोध यादा है। बिहार में कई ट्रेनों में आग लगाई गई है। अपनी मांगों मनवाने का यह तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है लेकिन 4 साल की नौकरी के सरकार के ऑफर पर नौजवान हिंसा पर उतारू हो गए हैं। विरोध बढ़ता देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि नई योजना से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है और अग्निवीरों की आयु सीमा बढ़ा दी गई है। कुछ दिनों में भर्ती प्रिया शुरू होगी। नई



योजना युवाओं को देशसेवा का सुनहरा मौका देगी। युवाओं की एक नाराजगी इस बात को लेकर थी कि दो साल से कोई भर्ती नहीं हुई और अब नई स्कीम के आने से वे

उम्र सीमा से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने कुछ घंटे पहले घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर

23 वर्ष करने के लिए एकमुश्त छूट प्रदान की है। पिछले दो वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। लेकिन नौजवान नहीं माने। वैसे, यह पहली बार





**देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने बकायदा प्रेस कांफ्रेंस करते हुए अग्निपथ योजना की खासियतों को बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने भरसक कोशिश की कि युवा इस योजना का स्वागत करें और योजना में भाग लेकर देश की सेवा करें, लेकिन बावजूद इसके देश के अंदर प्रदर्शन और हिंसाएं रूक नहीं पायी।**

नहीं है जब मोदी सरकार को 08 साल के भीतर अपने फैसले पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अबतक के दो बड़े फैसले उसे वापस भी लेने पड़े हैं।

2024 का लोकसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, पर कई राज्यों में चुनाव अगले कुछ महीनों में होने हैं। इससे पहले सरकार की छवि पर दाग लग रहा है। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना के विरोध में आग ही आग दिखाई दे रही है। मोदी सरकार ने साल 2022 के लिए इस प्रक्रिया के तहत भर्ती की उम्र पहले से घोषित 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि सभी नई भर्तियों के लिए आयु साढ़े 17 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, पिछले दो वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ, सरकार

ने फैसला किया है कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया के लिए एक बार में (आयु सीमा में) छूट दी जाएगी। सरकार स्पष्टीकरण जारी कर रही है लेकिन नौजवान को यह समझ में नहीं आ रहा है। सरकार ने कहा है कि नया मॉडल न केवल सशस्त्र बलों में नई क्षमता पैदा करेगा बल्कि यह युवाओं को लिए निजी क्षेत्र के रास्ते भी खोलेगा और उन्हें अवकाश प्राप्त करने के समय मिलने वाले वित्तीय पैकेज से उद्यमी बनने में भी मदद करेगा।

**उम्र के इस पड़ाव में कहा जायेंगे युवा-** मोदी सरकार जिस अग्निपथ योजना को युवाओं के वरदान बता रही है वो युवाओं के लिए अभिशाप बन जायेगी। क्योंकि अपनी पढ़ाई छोड़ नौकरी करने आए युवा जब 04 साल बाद सेना से बाहर निकल दिए जायेंगे। उस वक्त उनके साथ

कौन खड़ा होगा, क्या रोजगार होगा, कैसे वो अपना और परिवार के लोगों का पालन पोषण करेगा। जब तक केंद्र सरकार इन सभी सवालों के जवाब युवाओं को नहीं देती उन्हें इस योजना को लागू करने का अधिकार नहीं है।

**पहली समस्या चार साल ही क्यों?-** प्रदर्शन कर रहे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि सिर्फ चार साल के लिए ही क्यों भर्ती की जा रही है। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी कम से कम 10 से 12 साल की सर्विस होती है और आंतरिक भर्तियों में उन सैनिकों को मौका भी मिल जाता है। अग्निपथ योजना में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि चार साल के बाद 75 पर्सेंट युवाओं को बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा। जहानाबाद में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का



कहना है, सिर्फ चार साल नौकरी करने के बाद हम कहां जाएंगे। चार साल की सर्विस के बाद तो हम बेघर हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए। आर्मी से रिटायर और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। युवाओं की चिंता है कि चार साल के बाद वे क्या करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि साढ़े 17 साल में अग्निवीर बनने वाले युवा के पास न तो कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी और न ही कोई विशेष योग्यता, ऐसे में वह दोयम दर्जे की नौकरियों के लिए बाध्य होगा।

**कहीं कृषि कानूनों की तरह न हो जाए अग्निपथ का हथ्र**

अग्निपथ योजना मामले में युवाओं में



प्रतिरोध फैला, बड़े पैमाने पर तेजी से इकट्ठा होकर युवा सड़कों पर उतर आए और हिंसा भी शुरू कर दी। योजना को लेकर देश के सात राज्यों में जिस तरह से हिंसक विरोध जारी है, उससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस योजना का हथ्र भी कहीं कृषि

कानूनों की तरह तो नहीं होगा? इसका एक बड़ा कारण योजना के विरोध के पहले दिन ही सरकार का बैकफुट पर जाकर अग्निवीर भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल करना है। हालांकि यह केवल एक साल के लिए ही किया गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि कोरोना काल में सेना में भर्ती न हो पाने की वजह से ऐसा किया गया है। लेकिन यह प्रावधान तो योजना लाते समय ही किया जाना चाहिए था। दो साल से सेना में भर्तियां नहीं हुई हैं, यह तो सरकार को पहले से मालूम था। अगर युवाओं का यह हिंसक प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहा तो मुमकिन है कि योजना में और भी संशोधन होते चले जाएं।





# यूनिवर्सिटियों के चांसलर को लेकर फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में तकरार

**अमित राय**

पश्चिम बंगाल में राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री होंगी। इस संबंध में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक विधेयक पारित हुआ है। इसमें राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य की ओर से चलाए जाने वाले सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी चांसलर बनाने का प्रावधान किया गया है। इस कदम के बाद शिक्षा जगत में हंगामा

मच गया है। कुछ शिक्षाविदों ने इसका तीखा विरोध किया है। उन्हें लगता है कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खतरे में पड़ जाएगी। यही नहीं, उनका मानना है कि यह लोकतंत्र की भावना के भी खिलाफ है। आखिर बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलरों के संबंध में मौजूदा नियम क्या कहते हैं? क्या ममता ने जो कदम उठाया है वो संविधान के अनुसार है? आइए, यहां इन सभी सवालों

के जवाब जानते हैं।

**कौन होता है राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर?**- देश के तमाम राज्यों में ज्यादातर राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर या कुलाधिपति गवर्नर होते हैं। इसके उलट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन, सभी विश्वविद्यालयों में चांसलर होना जरूरी है। फिर चाहे वो राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय हों या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज।

**क्या सिर्फ राज्यपाल ही बन सकते हैं**

## ममता के कदम का क्यों हुआ है विरोध ?

पश्चिम बंगाल की जानी-मानी हस्तियों के एक समूह ने ममता के कदम का विरोध किया है। इनमें एक्टर कौशिक सेन, डायरेक्टर अनिक दत्ता और राजा सेन, चित्रकार समीर आइच, अभिनेता बिभास चवर्ती, सामाजिक कार्यकर्ता मिरातुन नाहर और मानवाधिकार कार्यकर्ता सुजातो भद्र जैसे 40 लोग शामिल हैं। इन्होंने इस कदम पर असंतोष जाहिर किया है। उनका कहना है कि इस कदम से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को झटका लगेगा। इसे उन्होंने लोकतंत्र की भावना के खिलाफ भी बताया है। ये चाहते हैं कि कुलाधिपति के पद पर एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद को नियुक्त किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, अगर कुलाधिपति के पद पर किसी शिक्षाविद की नियुक्ति की जाती है तो इससे संस्थानों के संचालन में बाहरी हस्तक्षेप को रोका जा सकेगा।

राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर?— नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति या राज्यपाल चाहें तो चांसलर नियुक्त भी कर सकते हैं। इस तरह राज्यपाल का ही राज्य

विश्वविद्यालयों का चांसलर होना जरूरी नहीं है। यहां एक और बात ध्यान रखने वाली है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर राज्य

और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार के बनाए कानूनों को राज्य सरकार को अनिवार्य तौर पर स्वीकार करना पड़ता है। अगर किसी राय के





विधानमंडल का बनाया कानून संसद के बनाए कानून के प्रावधान के खिलाफ है तो वह शून्य हो जाता है। यानी ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया है उस पर संसद में कानून लाकर केंद्र सरकार पानी फेर सकती है। इसी का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेदु अधिकारी ने इस मुद्दे को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजने की बात कही है। शिक्षा समवर्ती सूची में आती है।

**प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के क्या नियम हैं ?** - प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के नियम राज्यों और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नियमों से कुछ अलग हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों का चांसलर उसका फाउंडर या अध्यक्ष होता है। उस मामले में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का दखल नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम उत्तर प्रदेश के रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को ले सकते हैं। इसमें चांसलर आजम खान हैं। इस यूनिवर्सिटी का गठन 2006 में हुआ था।

**क्या प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं यूनिवर्सिटी के चांसलर ?** - जी, यह सच है। हालांकि, आप इसे अपवाद की श्रेणी में भी रख सकते हैं। बंगाल में विश्व भारती देश की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहां प्रधानमंत्री चांसलर होते हैं। विश्व भारती को 1951 में संसद के एक कानून के जरिये सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया था। इस यूनिवर्सिटी में विजिटर (परिदर्शक) राष्ट्रपति होते हैं। वहीं, रेक्टर (प्रधान) पश्चिम बंगाल के गवर्नर होते हैं। राष्ट्रपति यूनिवर्सिटी के उपाचार्य यानी वाइस चांसलर को नियुक्त करते हैं। इस तरह फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उनके पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय के चांसलर थे।

**राज्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में**

## कितने मतों से पारित हुआ विधेयक, क्या दी गई दलील?

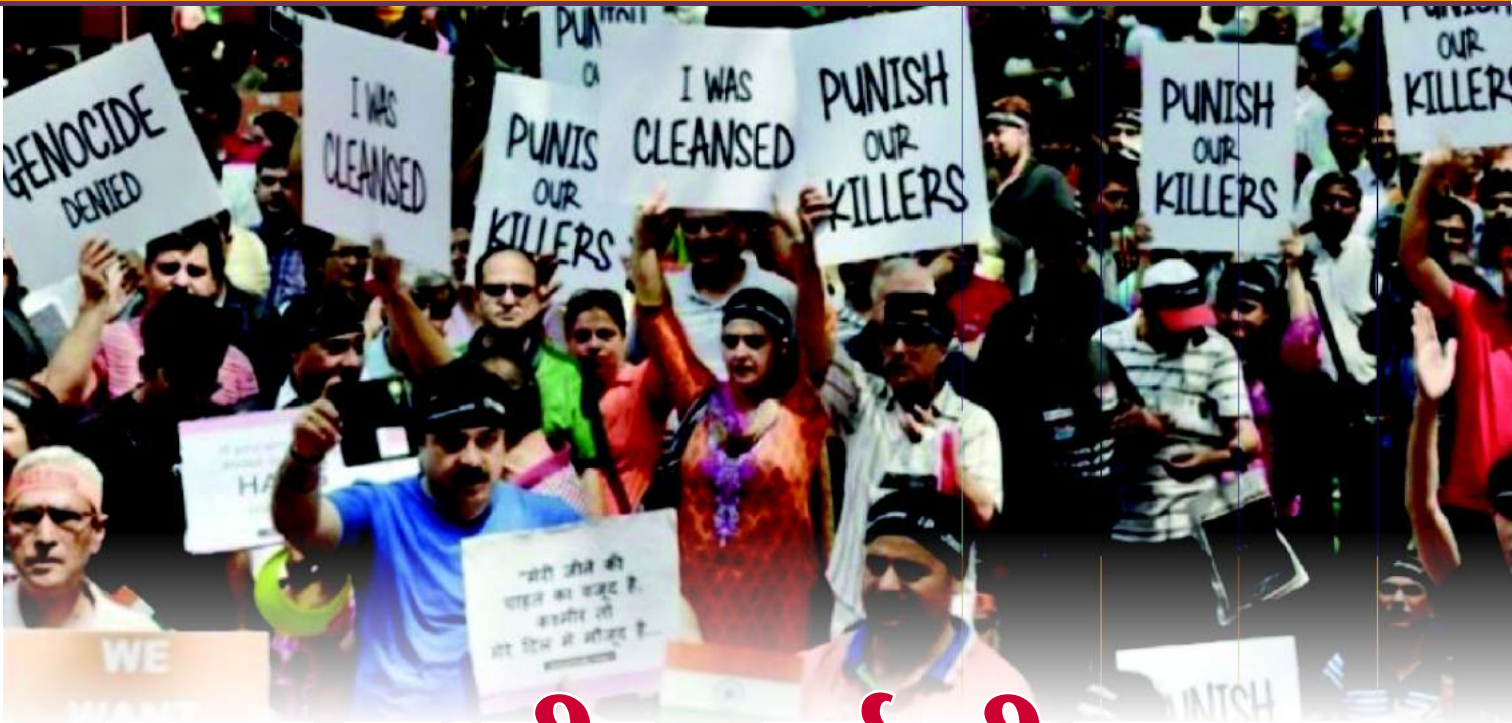
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति सीएम को बनाने वाला विधेयक 40 मतों के मुकाबले 182 सदस्यों के समर्थन से पारित हुआ। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2022 को सदन में पेश किया। इसके बाद कहा कि मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने में कुछ भी गलत नहीं है। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती के कुलाधिपति प्रधानमंत्री हैं तो सीएम राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति क्यों नहीं हो सकती? आप पुंछी आयोग की सिफारिशों का अवलोकन कर सकते हैं। पुंछी आयोग - 2010 ने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन किया जाना चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियों को वापस लेने का अधिकार देता है। शर्त यह है कि वह संतुष्ट हों कि ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिसमें राय की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

**गवर्नर के पास क्या पावर होती है ?** - ज्यादातर मामलों में राज्यपाल ही उस राज्य में विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं। राज्यपाल के तौर पर उन्हें काम करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की जरूरत होती है। हालांकि, चांसलर के तौर पर वह स्वतंत्र तौर पर काम करते हैं। यानी यूनिवर्सिटी के मामलों में फैसले लेने के लिए उन पर किसी का जोर नहीं होता है।

**कौन करता है चांसलर की नियुक्ति ?** - यूनिवर्सिटी के चांसलर को नियुक्त करने का नियम यूनिवर्सिटीज एक्ट से तय होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट, 2009 से इसका निर्धारण होता है। राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी में विजिटर होते हैं। वही इन विश्वविद्यालयों में चांसलरों की नियुक्त

करते हैं। चांसलरों की भूमिका कॉनवोकेशन की अध्यक्षता करने तक सीमित होती है। वाइस चांसलर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से गठित सेलेक्शन कमेटी इसके लिए कई नामों का सुझाव देती है।

**जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर के मामले में क्या हैं नियम ?** - जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मामले में राष्ट्रपति चांसलर नहीं होते हैं। जेएनयू चांसलर की नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत होती है। जेएनयू के मौजूदा चांसलर वीके सारस्वत हैं। वहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर उपराष्ट्रपति होते हैं। इस तरह अभी यह जिम्मेदारी वेंकैया नायडू के पास है।



# जम्मू-कश्मीर... दर्द की दास्तान सुनने वाला कौन?

## मणिशंकर पाण्डे

कश्मीर फिर हिंदुओं के खून से लहलुहान है। सिलसिलेवार हत्याओं ने 1990 के जख्म हरे कर दिए हैं। चुनचुनकर हिंदुओं के खून से होली खेली जा रही है। विजय कुमार, रजनी बाला, राहुल भट्ट जैसों को आतंकी दिनदहाड़े मारकर चल जाते हैं। मकसद सिर्फ यह खौफ भर देना है कि गैर-मुस्लिमों, बाहरियों और उनके हमदर्दों के लिए कश्मीर में जगह नहीं है। असर दिखने भी लगा है। बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदुओं ने पलायन शुरू कर दिया है। आखिर कौन हैं ये आतंकी जो इतनी आसानी से इन वारदातों को अंजाम दे देते हैं? क्यों इनकी

पहचान करना मुश्किल हो गया है? दरअसल, सरकार के पास भी इन सवालों के सटीक जवाब नहीं हैं। उसके सामने पहली बार एक अलग तरह की चुनौती खड़ी हो गई है। आतंकियों ने आतंक फैलाने के लिए अपना चेहरा बदल लिया है। अब ये हाइब्रिड टेररिस्ट का मुखौटा लगाकर दहशत फैलाने की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। एक मई से कश्मीर में 9 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। इनमें से तीन पुलिसकर्मी थे और 6 निर्दोष नागरिक। टारगेट किलिंग की इन सिलसिलेवार घटनाओं ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है।

साल 2022 में एक बार फिर कश्मीर

से पलायन का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। एक बार फिर घाटी के लोग अपनी जमीन छोड़कर पलायन कर रहे हैं। अपना घर छोड़कर जाने का गम उनके चेहरे पर आसानी से पढ़ा जा सकता है। इनके गमगीन चेहरों पर आतंकी की स्याही ने खौफ लिख दिया है। पिछले कई दिनों में कश्मीर में 9 हत्याएं हो चुकी हैं। इन आतंकियों ने एक-एक करके लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब वहां के लोग ये कहते हुए जा रहे हैं कि हमें मरना नहीं है। 1990 को परिस्थितियां दूसरी थीं मगर अब परिस्थितियां दूसरी हैं। साल 2020 में घाटी से धारा 370 को भी हटा दिया गया। कहा गया था कि इसके बाद



स्थितियां सुधरेंगी मगर हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। आतंकियों ने अब घाटी को छलनी करने के लिए एक अलग तरीका निकाला है। ये आतंकी अब बड़ी-बड़ी रायफल्स के साथ नहीं बल्कि छोटी पिस्टल, माउजर के साथ टारगेट किलिंग शुरू कर दी। अब इसका जिम्मेवार कौन होगा। कश्मीर के हालात कब सुधरेंगे। क्या कभी बाकी राज्यों की तरह कश्मीर हो पाएगा। हमारे बच्चों का भविष्य यहां क्या है। घर से निकलने में भी 100 बार सोचना पड़ता है। कभी-कभी तो इतनी फोर्स देखकर लगता है कि क्या हम अपने ही मुल्क में हैं। अनगिनत सवाल लोगों के जेहन में उबाल मार रहे हैं मगर जवाब किसी के पास नहीं है। 2 जून यानी एक दिन पहले ही राजस्थान के विजय कुमार को गोली मार दी गई। वो बैंक में मैनेजर

आतंकियों ने अब घाटी को छलनी करने के लिए एक अलग तरीका निकाला है। ये आतंकी अब बड़ी-बड़ी रायफल्स के साथ नहीं बल्कि छोटी पिस्टल, माउजर के साथ टारगेट किलिंग शुरू कर दी। अब इसका जिम्मेवार कौन होगा। कश्मीर के हालात कब सुधरेंगे। क्या कभी बाकी राज्यों की तरह कश्मीर हो पाएगा। हमारे बच्चों का भविष्य यहां क्या है। घर से निकलने में भी 100 बार सोचना पड़ता है। कभी-कभी तो इतनी फोर्स देखकर लगता है कि क्या हम अपने ही मुल्क में हैं। अनगिनत सवाल लोगों के जेहन में उबाल मार रहे हैं मगर जवाब किसी के पास नहीं है। 2 जून यानी एक दिन पहले ही राजस्थान के विजय कुमार को गोली मार दी गई। वो बैंक में मैनेजर थे।

थे। नौकरी लगी तो सभी को खुशी हुई मगर जब बेटे की लाश उनके चौखट पर रखी तो मां, बाप के मुंह से सिर्फ एक ही बात बार-बार निकल रही थी अच्छा होता नौकरी छोड़कर घर आ गया होता। नमक रोटी खा लेते मगर सुकून से सब साथ तो रहते।

कुछ महीने पहले देश में एक फिल्म सनसनी की तरह फैली। इस फिल्म का

नाम था द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स की कहानी आग की तरह फैली और फिर थियेटर में भारी भीड़। भावनाएं चरम पर थी। थियेटर के अंदर ही जिंदाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगने लगे और लोगों के भावुक होने की तस्वीरों से सोशल मीडिया भर गया। फिर लोगों के अंदर एक गुस्सा पनपा और 1990 के दौर को याद





करने लगे। याद ही याद में यादों का कारवां सड़कों तक आया फिर मांग हुई की कश्मीरी पंडितों के साथ जिन्होंने जघन्य अपराध किया उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बात के कुछ दिन बीत गए मगर फिल्म की दुनिया से अलग अब उसी कश्मीर की घाटी की अलग-अलग तस्वीरें

लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर रही हैं। दुर्भाग्य तो देखिए, हमारे अपने देश में ही अपनों को ही अपना वतन छोड़ना पड़ रहा है। 1990 की तस्वीर आपने या तो किताबों में पढ़ी होगी या फिर तमाम फिल्मों में देखी होगी। मगर विवेक अग्निहोत्री की हाल ही आई फिल्म ने उस तस्वीर को

ज्यादा संजीदगी के साथ लोगों के सामने पेश किया। इसके बाद 1990 कश्मीरी पंडितों के पलायन को 1990 नरसंहार कहा गया। 1990 के बाद साल 2022 का समय आया। अब तक 32 साल का वक्त बीत चुका था। मगर घाटी अब भी लहुलुहान है। वो तमाम शायरों के अल्फ़ाज़ भी खामोश होते गए। वो घाटी जिसके सम्मान के लिए भारत मां के न जाने कितने वीर योद्धा हंसते-हंसते शहीद हो गए आज उसी घाटी को घायल किया जा रहा है। 1990 के बाद 2022 में कुछ ऐसा ही हो रहा है।

1990 की कहानी दोहराई जा रही है बस किरदार अलग हैं और हालात अलग हैं। तब खुले आम आतंकी घरों में घुसकर लोगों को मार रहे थे, महिलाओं के रेप हो

1990 के बाद साल 2022 का समय आया। अब तक 32 साल का वक्त बीत चुका था। मगर घाटी अब भी लहुलुहान है। वो तमाम शायरों के अल्फ़ाज़ भी खामोश होते गए। वो घाटी जिसके सम्मान के लिए भारत मां के न जाने कितने वीर योद्धा हंसते-हंसते शहीद हो गए आज उसी घाटी को घायल किया जा रहा है। 1990 के बाद 2022 में कुछ ऐसा ही हो रहा है।





रहे थे, मगर अब ये आतंकी छिपकर एक खास हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हत्याएं हुई हैं वो इस बात का सबूत है कि किस तरह सिस्टम को ये आतंकी चैलेंज कर रहे हैं। धारा 370 के बाद कश्मीर में आतंक के आकाओं को मारा गया। सरकार ने वहां की स्थिति को नॉर्मल करने के लिए तमाम कार्यक्रम किए। सेना ने कई ऑपरेशन चलाए। इन सबका असर ये हुआ कि आतंकी अब हमले नहीं कर पा रहे हैं। सेना से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद आतंकी कायराना हरकतों में उतारू हो गए हैं।

### कैसे अपने मंसूबों में सफल हो रहे आतंकी?

इस साल व पुलिसकर्मी इन आतंकीयों का निशाना बन चुके हैं। वहीं, 2021 में 20 ने जान गंवाई थी। जिन कैंपों में माइग्रेंट वर्कर रहते हैं वहां सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं। लेकिन बिगड़ते माहौल को देखकर वो कश्मीर छोड़कर अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। ज्यादातर लोगों को

आतंकीयों ने उस वक्त टारगेट बनाया जब वो या तो अपने काम पर जा रहे थे या काम करके लौट रहे थे। इस तरह आतंकी अपने मंसूबों में सफल होते दिख रहे हैं। वो यही चाहते हैं।

### क्या है इस चुनौती का हल?

इस तरह की खबरें हैं कि प्रशासन के सामने हत्याओं को अंजाम देने वालों की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी वजह यह है कि दहशत फैलाने वाले आतंकीयों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब कश्मीर में हिंदुओं में खौफ पैदा करने के लिए पाकिस्तान से एके-47 भेजने का बहुत जोखिम नहीं लिया जा रहा है। अलबत्ता, कश्मीरी युवाओं को ही उकसाकर उनके हाथों में पिस्टल थमाई जा रही हैं। अक्सर थोड़े से पैसे या ड्रग्स का लालच देकर इनसे हत्याओं को अंजाम दिलाया जाता है। प्रशासन का मानना है कि इसमें पुलिस फोर्स बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रशासन स्थानीय पुलिस कर्मियों

को तैयार करेगा कि वे छोटे-मोटे अपराध करने वालों पर नजर रखें। उनकी भी पहचान की जाए जिनका व्यवहार असामाजिक है और जिनका रुझान आपराधिक गतिविधियों की तरफ है।

### क्यों है इन आतंकीयों के बारे में पता लगाना मुश्किल

इन हाइब्रिड टेररिस्टों के बारे में पता लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनका अपराध का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं होता है। ये हथियार चलाने की मामूली ट्रेनिंग लेकर वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए अमूमन ऐसे कश्मीरी युवाओं को ही चुना जाता है जिनका अपराध की ओर झुकाव होता है। इन्हें उकसाकर और मामूली पैसे का लालच देकर निर्दोषों की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया जाता है। हमला करने के बाद ये बड़ी आसानी से दोबारा भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं।

### इसके पीछे का प्लान



### समझिए...

यह पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों के आकाओं के लिए बहुत मददगार है। वो आसानी से इन आतंकी वारदातों की जिम्मेदारी लेने से मुकर सकते हैं। यह पाकिस्तान को मौका देता है कि वह इसे कश्मीरियों को विद्रोह बताकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पल्ला झाड़ ले। यानी पाकिस्तान और उसके आंगन में पलने वाले आतंकियों दोनों के लिए यह विन-विन सिचुएशन है। इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर पाकिस्तान कश्मीर में आग सुलगाए रखने के साथ आसानी से अपना दामन दागदार होने से बचा सकता है। वहीं, सच यह है कि पाकिस्तान सीमा पार से हर दिन पिस्टलों का कंसाइनमेंट भेज रहा है। इनमें कई पकड़े गए हैं। हालांकि, कई हाइब्रिड टेररिस्टों के हाथों तक पहुंच जाते हैं।

### कश्मीर मसले पर विरोध में खुले मुंह

अब कश्मीर मसले पर सरकार के

खिलाफ विरोधियों के मुंह खुल गए हैं। दरअसल, आतंकियों ने पिछले कुछ समय में कश्मीर में चुन-चुनकर गैर-मुस्लिमों की हत्याएं की हैं। हत्याओं का यह दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकियों ने कुलगाम में जम्मू के सांबा जिले की रहने वाली एक महिला शिक्षक सहित तीन लोगों की हत्या कर दी थी। 18 मई को आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक शराब की दुकान में घुसकर ग्रेनेड फेंका था। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तीन अन्य घायल हो गए थे। 24 मई को श्रीनगर में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके ठीक दो दिन बाद बडगाम में एक टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 12 मई को आतंकियों ने कश्मीर के बडगाम जिले के चदूरा इलाके में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी। इसके बाद से कश्मीरी पंडित सहमे हुए

हैं। वो न केवल सरकार का विरोध करने लगे हैं बल्कि पलायन करने पर भी मजबूर हुए हैं। कश्मीर में सुरक्षा के मसले पर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है।

### कैसे सरकार की छवि को लग रहा है बढ़ा?

कश्मीर से हिंदुओं का पलायन और उनमें डर की भावना बैठना कतई अच्छी खबर नहीं है। यह आतंकियों की जीत है। वो यही चाहते थे। यह सरकार पर भी सवाल खड़े करता है। इससे पता चलता है कि वह अपने वादे को पूरा करने में कामयाब नहीं हुई है। कश्मीर की ताजा घटनाएं हों या बंगाल और दिल्ली दंगों की वारदातें, इसने सरकार के लिजलिजेपन को दिखाया है। ये सभी बीजेपी की छवि पर बढ़ा लगाने वाली हैं।



# महाराष्ट्र की राजनीति के नये किंगमेकर बने एकनाथ शिंदे

## समता पाठक

महाराष्ट्र में 10 दिनों से भी अधिक समय से पहले शुरू हुआ सियासी ड्रामा आखिरकार अब शांत हो गया। महाराष्ट्र की सियासत में आये इस भूचाल की शांति शिवसेना प्रमुख और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ हुई। सियासी गहमागहमी के इस भूचाल को हवा देने वाले एकनाथ शिंदे आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गये। लेकिन शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे देवेन्द्र फडणवीस की मुख्यमंत्री बनने की सभी अटकलें पर रोक लग गई और उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा है। देखा जाए तो लोकतंत्र में सरकार गिराने और बनाने का सिलसिला पिछले कुछ समय से तेजी से चल रहा है। यूँ कहें कि सबसे कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काबिज हुए तभी से नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की जुगलबंदी ने बगैर भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों को सरकार चलाने में कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यही कारण है कि पहले

मध्यप्रदेश और अब महाराष्ट्र में भाजपा ने गैर भाजपाई सरकारों को गिराकर भाजपाई सरकार बनाने का सिलसिला शुरू किया।

## सूरत पहुंचे थे बागी विधायक

जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव में शिवसेना के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद ही उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक बुलाई थी। जिसमें सभी शिवसेना के विधायकों को हर हाल में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। लेकिन शिवसेना के नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे बैठक में नहीं पहुंचे और उनके साथ पार्टी के 11 विधायक भी नदारद रहे। उसी दिन शिवसेना के एक दर्जन से अधिक विधायक सूरत पहुंच गए।

## 40 विधायकों का समर्थन

शिवसेना के भीतर बगावत की खबर सामने आई शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को पार्टी के विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया। इसके बाद शिवसेना की एनसीपी और कांग्रेस के साथ बैठक हुई। इस बीच शिवसेना के बागी विधायक





सूरत से अहम के गुवाहाटी पहुंच गए और होटल रैंडिसन ब्लू में एक साथ नजर आए। होटल रैंडिसन में एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है, जोकि दल बदल कानून को उनके ऊपर लागू नहीं होने देने के लिए पर्याप्त है।

### ठाकरे ने की थी अपील

महाराष्ट्र में सियासी संकट बढ़ने के साथ ही उद्धव ठाकरे ने लोगों बागी विधायकों के साथ जनता को संबोधित किया और कहा कि अगर बागी विधायक चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं और इसके बाद

उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया। इसके बाद एनसीपी चीफ शरद पवार, सुप्रिया सुले, जितेंद्र अह्वाड ने ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें पूरा समर्थन देने की बात कही।

### महाराष्ट्र के सियासत के यह है पांच मोहरे

**एकनाथ शिंदे-** शिंदे ने बगावत कर महाराष्ट्र सरकार को संकट में डाल दिया है। 18 साल की उम्र से शिवसैनिक हैं। बालासाहेब ठाकरे और ठाणे में शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दिघे के निष्ठावान रहे हैं। एक जमाने में रिक्शा चलाते थे। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। बेटा शिवसेना

सांसद है और शिंदे खुद चार बार विधायक रहे हैं। शिंदे शिवसेना के एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने से नाराज थे।

**उद्धव ठाकरे-** उद्धव ठाकरे शिवसेना के पार्टी प्रमुख हैं और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के गठबंधन वाली महा विकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री थे। 2014 में बीजेपी ने शिवसेना से गठबंधन तोड़ा था। बदले में इन्होंने 2019 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ उसे सत्ता से दूर कर दिया और एनसीपी-कांग्रेस के साथ मिलकर पिछले ढाई साल से गठबंधन सरकार चला रहे हैं। कभी बीजेपी के प्रमुख सहयोगी रहे उद्धव इस समय बीजेपी के प्रमुख



आलोचकों में से एक हैं।

**संजय राउत-** शिवसेना के रायसभा सांसद है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादक है। राउत शिवसेना का राष्ट्रीय चेहरा हैं। शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस का गठबंधन बनाने में इनकी मुख्य भूमिका रही है। संजय राउत उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के करीबी हैं। पिछले कुछ वर्षों में शिवसेना का पावर सेंटर बन गए हैं। इसके बाद से शिवसेना में भी इनके कई विरोधी पैदा हो गए हैं।

**मिलिंद नावेंकर-** उद्धव ठाकरे के निजी सहायक हैं, शिवसेना के सचिव हैं। शिवसेना के पावर सेंटरों में से एक और ठाकरे परिवार के संकटमोचक माने जाते हैं। उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे तथा राज्य के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे के बेहद विश्वासपात्र हैं।

उद्धव ठाकरे के साथ साए की तरह रहते हैं। एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने इन्हीं को सूत्र भेजा था। लेकिन वो भी शिंदे को मना पाने में नाकामयाब रहे।

**देवेंद्र फडणवीस-** महाराष्ट्र की राजनीति के नए चाणक्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। संगठन पर मजबूत पकड़ है। अपने विरोधियों को प्यार से ठिकाने लगाने में माहिर हैं। उद्धव ठाकरे का तख्तापलट करने के लिए पिछले ढाई साल से लगातार कोशिश की। एकनाथ शिंदे की बगावत के पीछे भी इन्हीं की रणनीति ने काम किया।

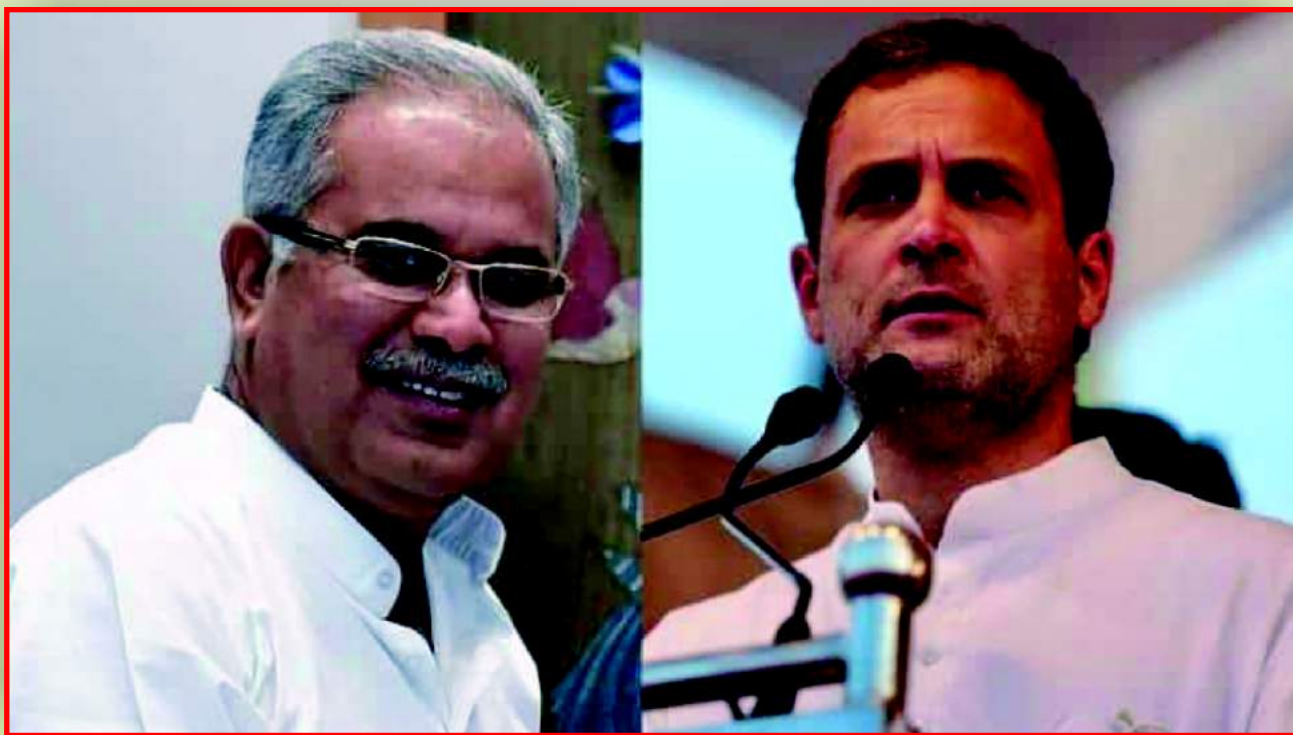
### **छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर अटकलें शुरू**

महाराष्ट्र में सफल हुए ऑपरेशन लोटस के बाद अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है

कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन से सचिन पायलट बहुत अधिक संतुष्ट नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल छत्तीसगढ़ का भी है जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्णयों से प्रदेश के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सरकार है और भाजपा के शीर्षस्थ नेता सिर्फ इस बात को ही ताकती है कि कहीं भी कांग्रेस सरकार का कमजोर दरवाजा दिखे और वो उस दरवाजे को उखाड़कर सीधे सत्ता में प्रवेश करने का रास्ता बनाना शुरू कर देती है। देखा जाए तो राजनीति में सब कुछ जायज है, लेकिन इस तरह से खरीद-फरोख्त और सत्ता का लालच देकर कुर्सी हथिया लेना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है।



# राहुल गांधी पर ईडी का एक्शन और छत्तीसगढ़ कनेक्शन



## विजया पाठक

राहुल गांधी पर ईडी द्वारा की जा रही कार्यवाही के पीछे छत्तीसगढ़ कनेक्शन की बात उठ रही है और इसके पीछे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी पर ईडी की कार्यवाही की सच्चाई समझने के लिए हमें

कुछ साल पीछे चलने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह की सरकार थी। उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी को प्रदेश में तीन कोयला जिसमें से दो खदान के माइन डेवलपर कम ऑपरेटर हैं उनकी आवंटन करने की प्रक्रिया चल रही थी। खदानें आवंटित भी हो गईं लेकिन

एनओसी नहीं मिलने के कारण खदानें चालू नहीं हो पायी थी। एनओसी मिलती इससे पहले रमन सरकार चली गई और इसी बीच प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार बन गई। भूपेश सरकार में इन तीन खदानों के आवंटन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर खूब विरोध प्रदर्शन हुए। स्थानीय स्तर



**नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पिछले दिनों ईडी ने राहुल गांधी से लंबी पूछताछ की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली में डेरा डाले रहे। बघेल शायद जता रहे थे कि वे पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। लेकिन परदे के पीछे की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है।**

पर भी कई स्वयंसेवी संगठनों में विरोध किया। लेकिन लगभग तीन साल बाद 2022 में भूपेश सरकार ने तमाम बाधाओं को दूर करते हुए और तमाम विरोधों के बाद अडानी ग्रुप को हसदेव क्षेत्र की तीन कोयला खदानों पर कार्य करने की अनुमति दे दी है। आप को बता दें कि इन खदानों को आवंटित करने का विरोध राहुल गांधी ने भी किया था। पर भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की बात को भी नहीं माना। वर्तमान में इन खदानों पर ग्राम पंचायत द्वारा रोक लगाई गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में इन खदानों का आवंटन खतरे में पड़ सकता है।

राहुल गांधी का हसदेव कोयला खदान को अडानी को आवंटित न करने की बात करना और भूपेश बघेल को एनओसी न देने की बात कही। राहुल गांधी ने 23 मई जगत विजन

2022 को लंदन की केंब्रिज यूनिवर्सिटी में युवाओं से बातचीत के दौरान हसदेव जंगल कटाई के बारे में प्रश्न पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी के हसदेव कोयला विस्तार योजना पर दिक्कत है। बस बीजेपी

**खदानों को आवंटित करने का विरोध राहुल गांधी ने भी किया था। पर भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की बात को भी नहीं माना। वर्तमान में इन खदानों पर ग्राम पंचायत द्वारा रोक लगाई गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में इन खदानों का आवंटन खतरे में पड़ सकता है।**

को राहुल गांधी का यही विरोध नागवार गुजरा। यही वह समय था जब राहुल गांधी को बीजेपी सरकार ने ईडी के माध्यम से परेशान करने का चक्रव्यूह रचा। भूपेश बघेल ने भी कई मौकों पर राहुल गांधी के विरोध की बातें कहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक 13 मई 2022 को गृहमंत्री अमित शाह से भूपेश बघेल से हुई मुलाकात में इन्होंने इशारे से मामले में राहुल गांधी के वीटो होने की बात कह दी। इसी से राहुल गांधी के खिलाफ शायद ईडी का चव्यूह रचा गया। इससे पहले भी 22 अक्टूबर 2021 को भूपेश बघेल ने अमित शाह से मुलाकात की थी। दरअसल ईडी तो बहाना भर है इससे राहुल गांधी को बैकफुट पर करने का बस एक तरीका है और यह पूरा खेल परदे के पीछे बैठकर भूपेश बघेल रच रहे हैं। भूपेश बघेल और इनकी चौकड़ी के 03 सदस्य के

जुलाई-2022



के खिलाफ करीब-करीब पूरी पार्टी को दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय ले जाकर भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगवाए। दिल्ली मीडिया में राहुल, सोनिया प्रियंका की न्यूज आए ना आए पर भूपेश बघेल पोस्टर बॉय बने हुए हैं। उत्तरप्रदेश चुनावों में सबसे बड़े कट आउट इनके लगे थे। ऐसे कई मौकों पर उन्होंने पार्टी हाईकमान को नीचा दिखाया है।

**गांधी परिवार को करीबियों ने ही नुकसान पहुंचाया!**

इतिहास गवाह है कि गांधी परिवार के नेताओं को उनकी करीबी ने सबसे यादा नुकसान पहुंचाया। वही इतिहास अब वापस चरितार्थ होने जा रहा है पर इस बार किरदार अलग है। इसकी नोबिलिटी समझनी होगी। दिसंबर 2018 राहुल गांधी ने टीएस बाबा, चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू की जगह भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया। तब छत्तीसगढ़ के पावर गैलरी में भूपेश के करीबी मुख्यमंत्री बनने के पहले कहते थे बस एक बार भूपेश मुख्यमंत्री बन जाए वो सबको पीछे छोड़ देंगे। आज करीब 3.5 साल बात सच होते भी दिख रही है। आज भूपेश बघेल से यादा आर्थिक संसाधन वाले नेता पूरे कांग्रेस में नहीं है। इसके लिए वो सारी बातें-मुद्दे जो सरकार से विपक्ष में रहते लड़ते थे, उसकी उन्होंने तिलांजलि दे दी। अपने आसपास ऐसी चौकड़ी बनाई जिसने छत्तीसगढ़ लूट-लूट कर खोखला बना दिया। जिस अदानी को भाजपा सरकार में जी भरकर कोसा करते थे उनके काम इस नवा छत्तीसगढ़ में सबसे पहली प्रायरीटी में होते हैं, इसका सीधा अर्थ तो यह है कि भूपेश बघेल तब विपक्ष में रहते गलत थे या अब मुख्यमंत्री बनकर गलत है। प्रदेश में अवैध शराब टैक्स हो या अवैध कोयला टैक्स किसी भी क्षेत्र को लूटने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। क्या भोले-भाले आदिवासियों का प्रदेश छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल लूट लेंगे?

मामले सुप्रीम कोर्ट, ईडी के पास विचाराधीन हैं और केंद्र कभी भी इनकी गर्दन मरोड़ सकती है। पर केंद्र सरकार की भूपेश पर मेहरबानी पिछले साढ़े तीन साल से मिली हुई है वरना यह अभी जेल में होते। यहीं कारण है कि आजकल सब जगह एक ही बात कहीं जा रही है कि राहुल गांधी पर ईडी की कार्यवाही में छत्तीसगढ़ कनेक्शन है।

पिछले दिनों भूपेश बघेल से दिल्ली में मीडिया वालों ने चर्चा करते हुए पूछा कि क्या अड़ानी के खदान को राहुल गांधी ने निरस्त करने को कहा था जिसके चलते ईडी की पूछताछ राहुल गांधी से हो रही है। इस सवाल को टालते हुये भूपेश बघेल ने कहा कि अड़ानी से भी बड़ी सरकार होती है। जबकि सभी जान रहे हैं कि अड़ानी केन्द्र सरकार में कितने बड़े व्यक्ति हैं और उनकी खदान को राहुल गांधी के कहने पर निरस्त करने की बात कही जा रही है।

**कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुलाने**

### के पीछे की कहानी

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली पहुंचने को कहा गया है। दरअसल इसके पीछे की कहानी कुछ अलग है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर जाने वाले थे किंतु उन्हें केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी। इसलिए वह विदेश दौरे पर ना जाकर दिल्ली के धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी तब भूपेश बघेल केवल अपने राजनीतिक सलाहकार और एक विधायक के साथ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। इन सब मामलों को देखकर तो यही लगता है इतिहास वापस दोहराने को है और गांधी परिवार पर कोई अपना ही पीठ पर खंजर मारेगा।

**अपने आप को पार्टी से उपर मानते हैं भूपेश बघेल**

आजकल वैसे भी भूपेश बघेल कांग्रेस में अपने बराबर किसी को नहीं समझते। बात पिछले साल की है जब टीएस सिंहदेव



# नीर के लिए पीर का स्थाई समाधान है जल जीवन मिशन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि देश की समूची ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उनके घर पर ही नल कनेक्शन के जरिये दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को अमल में लाने के लिए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन जारी की। इसके मुताबिक गाँव के हर परिवार को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। मिशन में यह प्रावधान रखा गया कि ग्रामीण आबादी में नल से जल उपलब्ध कराने पर होने वाला व्यय केन्द्र तथा राय

सरकार बराबर-बराबर वहन करेगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन की खूबियों को जाना और इसके सफल क्रियान्वयन के लिये अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनका मानना था कि ग्रामीण अंचल की माता-बहनों की नीर के लिए पीर को मिशन के माध्यम से हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान का संकल्प भी है कि मिशन से प्रदेश की करीब सवा 5 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के जरिए गुणवत्तापूर्ण जल की व्यवस्था समय-सीमा में हो जाए।

**बुरहानपुर बना शत-प्रतिशत नल-जल युक्त वाला प्रदेश का पहला जिला**

मध्यप्रदेश का बुरहानपुर ऐसा पहला जिला है जहाँ मिशन के माध्यम से शत-प्रतिशत ग्रामीण आबादी को उनके घर में नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध करवा दिया गया है। जिले के दोनों विकासखण्ड में 167 ग्राम पंचायतें और 254 ग्राम हैं। इन सभी गाँवों के प्रत्येक परिवार तक नल कनेक्शन से जल उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। सभी ग्रामीण परिवार मिशन से लाभान्वित होकर घर पर ही पेयजल की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। मिशन में प्रावधान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में संचालित सभी आँगनवाड़ी केन्द्र और

शालाओं में भी प्लेटफार्म बनाकर उनमें नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। अब आँगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों और वहाँ कार्यरत शासकीय अमले को गुणवत्तापूर्ण तथा पर्याप्त पेयजल उपलब्ध रहेगा।

प्रदेश में जून 2020 से जल जीवन मिशन में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को गति मिली और ग्रामीण परिवारों को नल से जल। इस तरह गाँव के हर घर में नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। अब सभी जिलों की ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने के कार्य तेज गति से चल रहे हैं। प्रदेश में बदलाव के साक्ष्य के रूप में मिशन में 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से निरन्तर जल प्रदाय शुरू हो गया है।

**मध्यप्रदेश का बुरहानपुर ऐसा पहला जिला है जहाँ मिशन के माध्यम से शत-प्रतिशत ग्रामीण आबादी को उनके घर में नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध करवा दिया गया है। जिले के दोनों विकासखण्ड में 167 ग्राम पंचायतें और 254 ग्राम हैं। इन सभी गाँवों के प्रत्येक परिवार तक नल कनेक्शन से जल उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है।**

मिशन से सभी स्कूलों और आँगनवाड़ियों में भी नल कनेक्शन से पेयजल प्रदान करने के अभियान में भी

तेजी से काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अब तक लगभग 69 हजार से अधिक शालाओं तथा 40 हजार से अधिक आँगनवाड़ियों में नल से जल सुलभ कराया जा चुका है। शेष स्कूल और आँगनवाड़ियों में नल से जल पहुँचाने का कार्य निरन्तर जारी है। जल जीवन मिशन में जल-संरचनाओं के निर्माण और संधारण के कार्य लगभग हर जिले में जारी हैं। ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल-प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने का सिलसिला बना हुआ है।

**4 हजार से अधिक ग्रामों में नल से जल**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम प्रदेश के सभी ग्रामीण अंचल के हर परिवार तक नल कनेक्शन से जल







पहुँचाने के लिये लगातार कार्य कर रहे हैं। विगत 22 माहों में प्रदेश के 4 हजार 143 ग्रामों के सौ फीसदी घरों में नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

### हर स्तर पर समितियाँ गठित

मिशन के संचालन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राय जल एवं स्वच्छता समिति, कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति और गाँव स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। योजना में निर्माण लागत की 10 प्रतिशत राशि जन-भागीदारी से जुटाने का प्रावधान है, जो श्रम, सामग्री अथवा नगद राशि के रूप में ली जा रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल ग्रामों में जन-भागीदारी का अंश 5 प्रतिशत रखा गया है।

### मिशन मार्गदर्शिका के घटकों के अनुरूप कार्य-संचालन

प्रदेश में मिशन के बेहतर संचालन के लिए मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रमुख रूप से चार घटकों





को शामिल कर उनके अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। प्रथम घटक - कार्य प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के अन्तर्गत दो टीमों गठित हैं। एक टीम तकनीकी सहायता तो, वहीं दूसरी टीम प्रबंधन समर्थन के लिए मैकेनिम पर काम कर रही है। जिला स्तर पर मिशन की सहायता के लिए जिला कार्यम प्रबंधन इकाई बनाई गई है। दूसरा घटक - कार्यान्वयन सहायता एजेन्सी (आईएसए) चयनित ग्रामीण क्षेत्र में जल-प्रदाय योजनाओं से प्रभावित समुदाय को सुविधा प्रदान करने, जन-सहयोग की सहमति लेने, बुनियादी ढाँचे के प्रबंधन के लिए गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को मार्गदर्शन देने का कार्य कर रही है। प्रत्येक जिले की अपनी कार्यान्वयन सहायता एजेन्सी है। तीसरा घटक - तृतीय पक्ष मूल्यांकन संस्थाएँ (टीपीआई) निरीक्षण के बाद यह तय करती है कि निर्माण संस्था द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कितना कार्य कर लिया है और किए गए कार्य के विरुद्ध संस्था को कितने भुगतान की पात्रता बनती है। चौथा घटक - कौशल विकास प्रशिक्षण के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी में स्थापित जल व्यवस्था का संचालन, संरक्षण और संधारण बेहतर हो सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है।

### एफटीके से जल परीक्षण का प्रशिक्षण

मिशन में ग्रामीण परिवारों को मिल रहा जल गुणवत्तापूर्ण है, इसकी समुचित जाँच के लिए स्थानीय महिलाओं को एफटीके से जल परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल-प्रदाय योजना का संचालन और संधारण बेहतर बनाये रखने के लिए वित्त प्रबंधन आवश्यक है। स्व-सहायता समूह की महिलाओं के सेक्टर वाइस क्लस्टर बनाकर उन्हें जल उपभोक्ता परिवारों से जलदर प्राप्त करने का दायित्व भी सौंपा गया है। जलप्रदाय योजनाओं के संचालन में भविष्य में आने वाली रूकावट अथवा



खराबी को स्थानीय स्तर पर दूर किया जा सके इसके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत स्थानीय युवाओं को समुचित प्रशिक्षण दिया जायेगा। जलप्रदाय योजना क्षेत्र के रहवासी करीब 50 हजार युवाओं को उनकी रूचि के अनुसार मैशन, पिलम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक तथा पम्प आपरेटर के कार्यों का प्रशिक्षण

देकर दक्ष बनाया जा रहा है। इससे जलप्रदाय योजनाओं को लेकर भविष्य में आई किसी भी कठिनाई को स्थानीय स्तर पर दूर किया जा सकेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

(लेखक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री हैं।)



# फिर लौटेगा गौ-सदनों का वैभव

मध्यप्रदेश गायों एवं गायों की सन्तानों (बछड़े-बछड़ियों, सांड-बैलों) के संरक्षण के लिए सर्वाधिक अनुकूल राय है। यहाँ का 951 हजार वर्ग किलो मीटर का जंगल गौ-वंश का आश्रय-स्थल है। सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रकृति और मूक-प्राणियों के मध्य एक नैसर्गिक समीकरण बना हुआ है। गायों का भोजन जंगल में और गोबर एवं गौ-मूत्र के रूप में जंगल का आहार गायों के पास। शासन-प्रशासन और आम नागरिकों को

मिलकर इस प्राकृतिक समीकरण के आधार पर गौ-वंश के संरक्षण एवं पालन की दिशा में युगानुकूल सम-सामयिक और नवाचार विधि से कार्य करना चाहिये।

## जंगलों में थे 10 गौ-सदन

अविभाजित मध्यप्रदेश के जंगलों में वर्ष 1916 से 10 गौ-सदन होते थे। वर्षा काल में लगभग 3 माह गौपालकों-कृषकों का पालित गौ-वंश जंगलों में बने इन्हीं 10 गौ-सदनों में निवास करता था। दीपावली

के आसपास इन गौ-सदनों से कृषकों-गौ-पालकों का गौ-वंश सकुशल घर वापस आ जाता था। प्राचीन भारत का यह किसानों की फसल सुरक्षा एवं गौ-वंश के संरक्षण का पारम्परिक रोडमैप हुआ करता था। ये गौ-सदन वर्ष 2000 तक व्यवस्थित संचालित होते रहे। गौ-सदनों के पास जंगलों में 7200 एकड़ चरनोई भूमि होती थी। वन विभाग की इस भूमि पर राय के पशुपालन विभाग का आधिपत्य रहा।





मध्यप्रदेश का विभाजन होने के बाद छत्तीसगढ़ राय अस्तित्व में आया और दो गौ-सदन (बिलासपुर और रायपुर के) छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से में चले गये। दुर्भाग्य से मध्यप्रदेश के 8 गौ-सदन अकारण ही भंग कर दिये गये। मध्यप्रदेश में गायों के समक्ष समस्या तब पैदा हुई जब मध्यप्रदेश के वर्ष 2000 और वर्ष 2003 के कालखण्ड के तत्कालीन शासन ने चरनोई भूमि की बंदरबाँट मनुष्यों में कर दी। जंगलों के गौ-सदन के भंग होने एवं नगरों और ग्रामों की चरनोई भूमि का

मनुष्यों में आवंटन ने मूक-प्राणियों, गौ-वंश आदि के जीवन को संकटग्रस्त कर दिया।

इधर तत्कालीन केंद्र शासन और राय शासन की माँस निर्यात नीति एवं कत्लखानों को धड़ल्ले से लाइसेन्स जारी करने की नीति ने प्रदेश के गौ-वंशीय तथा अन्य कृषिक पशुधन की महती हानि कर डाली। प्रदेश में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक सामाजिक एवं अन्यान्य संगठनों के सम्मिलित आन्दोलन, अनुष्ठान अभियान और प्रयासों से प्रदेश में पशुवध रोकने के कड़े कानून बने। आयोगों का गठन हुआ।

मध्यप्रदेश गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड बना। मालवा क्षेत्र के एक विशाल भू-खण्ड में कामधेनु गौ-अभयारण्य का निर्माण हुआ।

रादेश के मध्यभारत, बुंदेलखण्ड, बघोलाखण्ड एवं महाकौशल क्षेत्र में भी हमने मालवा क्षेत्र की भाँति अपने प्रयास सम्भावना के आधार पर आरम्भ कर दिये हैं।

प्रदेश में शासन की संकल्प शक्ति, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग और सयिता से तथा स्वयं सेवी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों से 627 स्वयं सेवी संगठनों की गौ-शालाएँ और 1265 गौ-शालाएँ मनरेगा के आर्थिक सहयोग से निर्मित ग्राम पंचायत स्तर पर यिशील हो गई हैं। एक गौ-वंश वन्य-विहार रीवा के बसावन मामा नामक स्थान पर तथा एक गौ-वंश वन्य-विहार जबलपुर जिले की कुण्डम तहसील में गंगईवीर जंगल परिक्षेत्र में निर्मित होने जा रहा है। इसी प्रकार जिला सीहोर के देलावाड़ी स्थान पर भी गौ-वंश वन्य विहार निर्माण की प्रिया जारी है।

हमें विश्वास है सरकार की नीति, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा शक्ति तथा मध्यप्रदेश गौ-संवर्धन बोर्ड की तत्परता से प्रदेश में गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्धन का अनुकूल वातावरण निर्मित होकर सकारात्मक और रचनात्मक ठोस परिणाम आगामी एक-दो वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे।

स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरिअध्यक्ष (कार्यपरिषद) म.प्र. गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड







# अब ईडी के निशाने पर गांधी परिवार

## क्या सत्ता की कठपुतली है जांच एजेंसिया ?

### समता पाठक

नेशनल हेराल्ड मामले का एक बार फिर सुर्खियों में है। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय निशाने पर गांधी परिवार है। नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले की जांच को लेकर ईडी एक्शन में है।

नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी लगातार पूछताछ हुई हैं। शुरुआती दो दिनों में उनसे 20 घंटे पूछताछ चली। सोनिया गांधी को भी जांच में शामिल होने के लिए तलब किया गया है। सोनिया और राहुल, ईडी के रडार पर आए पहले विपक्षी नेता

नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, केरल के लेफ्ट नेता, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन,

छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जम्मू और कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार... विपक्ष के उन नेताओं की लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान ईडी के ऐक्शन को कठघरे में खड़ा किया। विपक्षी नेताओं के निशाने पर सरकार के साथ-साथ एजेंसी भी रही।

### गांधी परिवार के लिए सड़कों पर कांग्रेस

राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होते वक्त कांग्रेस ने विरोध मार्च किया। कांग्रेसी नेताओं ने सत्याग्रह किया। केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के ईडी के सामने पेश होने पर दिल्ली में विरोध कर रहे थे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सरकार पर बरस रहे हैं और इसको लोकतंत्र का गला घोटना बता रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां हमेशा विपक्ष के निशाने पर होती



हैं। कांग्रेस के शासन में सुप्रीम कोर्ट ने तो सीबीआई को सरकार का तोता तक बोल दिया था। जब भी किसी नेता पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है तो वो इसका ठीकरा सरकार पर फोड़ देता है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। देश में कश्मीर ने कन्याकुमारी तक नेताओं को

ईडी का डर दिखाया जा रहा है। देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र हैं पूरा देश देख रहा है। आजादी के 76 साल बाद नया भारत बना है तो ये कांग्रेस की देन है। आजादी के पहले और बाद में कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाया। पूरे देश के अंदर आग लगी हुई है। ये लोग सत्ता के नशे में चूर है। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं।





# क्या है पूरा मामला

मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला 2010 में बनी गांधी परिवार के स्वामित्व वाली एक कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड से जुड़ा है जो 5 लाख की पूंजी से शुरू हुई थी लेकिन ईडी के मुताबिक आज उसके पास करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्ति है। वह भी तब जब कंपनी कथित तौर पर किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल भी नहीं है। संपत्ति में ये इजाफा सिर्फ एक सौदे की वजह से हुआ- नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण से। आइए समझते हैं पूरा मामला।

**पूरा मामला एक नजर में-**पूरे मामले को संक्षेप में समझें तो ये है कि 1938 में पंडित जवाहर लाल नेहरू की अगुआई में सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल)। मकसद था क्रांतिकारी अखबार शुरू करना और उनके जरिए आजादी की लड़ाई को तेज करना। कंपनी पर किसी एक शख्स का नियंत्रण या अधिकार नहीं था। कंपनी ने नेशनल हेराल्ड नाम से अंग्रेजी, कौमी आवाज नाम से उर्दू और नवजीवन नाम से हिंदी में अखबार निकालना शुरू कर दिया। एजेएल में नेहरू के अलावा 5000 दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी शेयर होल्डर थे। आजादी के बाद ये तीनों अखबार कांग्रेस के मुखपत्र बन गए। एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई, पंचकुला, लखनऊ और पटना में प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी थी। 2008 में एजेएल ने नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद कर दिया क्योंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। उस पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपये का कर्ज था। 2010 में भी एजेएल के 1057 शेयर होल्डर थे। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने एजेएल को खरीद लिया। खास बात ये कि ये कंपनी सिर्फ 3 महीने पहले ही 5 लाख रुपये की पूंजी से बनी थी और इसका स्वामित्व गांधी परिवार के पास था। सोनिया गांधी, उनके दोनों बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा के नाम यंग इंडियन लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयर हैं। इस तरह

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बनाई एक कंपनी और उसकी संपत्तियों पर एक परिवार का कब्जा हो गया।

**मामला कैसे सामने आया-** यंग इंडिया लिमिटेड ने असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के 99 प्रतिशत शेयर का अधिग्रहण कर लिया। मामला तब खुला जब एजेएल के कई शेयरहोल्डरों ने सौदे पर ये कहकर सवाल उठाया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नहीं दी गई और न ही उनकी सहमति ली गई जबकि शेयरहोल्डर के नाते ये उनका हक था। इन शेयरहोल्डरों में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और इलाहाबाद व मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मार्केंडेय काटजू भी शामिल थे। इन लोगों के पिता एलेएल में शेयर होल्डर थे इस नाते उनके निधन के बाद शेयरों पर उनका स्वामित्व था। दरअसल, सौदे से पहले ही 2010 में तमाम शेयर होल्डरों के शेयरों को एजेएल के नाम ट्रांसफर कर दिया गया, वो भी संबंधित शेयर होल्डरों को बिना कोई नोटिस या जानकारी दिए हुए। 2012-13 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी पूरे मामले को लेकर अदालत में चले गए। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एजेएल का अधिग्रहण गैरकानूनी तौर पर हुआ है। ये धोखाधड़ी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट (विश्वासभंगन) का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्यूटिडरू ने सिर्फ 50 लाख रुपये देकर एजेएल के 90 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली का अधिकार हासिल कर लिया और 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों का मालिकाना हक हासिल कर लिया।

**कहानी यंग इंडियन लिमिटेड की-** 2008 में एजेएल ने घाटे की वजह से अखबारों का प्रकाशन बंद कर दिया। उस वक्त उस पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपये का कर्ज था। इसी के बाद सीन में गांधी परिवार और उनके करीबियों की एंट्री होती है। नवंबर 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनती है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि उस

## नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के लिए कांग्रेसी बने ढाल

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के शीर्ष

नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों को कांग्रेस ने सिर से खारिज किया है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। एक राजनीतिक दल किसी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं खरीद

सकता। लिहाजा, यंग इंडियन के नाम से एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल्स (एजेएल) के शेयर दिए गए। इसका मकसद 90



वक्त केंद्र में कांग्रेस की अगुआई में यूपीए की सरकार थी। उस कंपनी के डायरेक्टर कोई और नहीं कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव राहुल गांधी थे। YIL में राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी का 76 प्रतिशत शेयर है। बाकी बचे 24 प्रतिशत शेयर गांधी परिवार के करीबियों मोतीलाल वोरा (2020 में निधन हो गया) और ऑस्कर फर्नांडीज (2021 में निधन) के नाम था।

**यंग इंडियन कंपनी के वजूद में आने से पहले ही उसे हासिल हो गई थी टैक्स छूट !-** यंग इंडियन कंपनी को कंपनी एक्ट की धारा 25 के तहत टैक्स जमा करने की छूट मिली हुई थी। इसका आधार ये रहा कि ये कंपनी एक चैरिटेबल नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन है। 29 मार्च 2011 को यंग इंडियन लिमिटेड ने इनकम टैक्स से छूट पाने के लिए आवेदन दिया। तब केंद्र में कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार थी। 9 मई 2011 को YIL की अर्जी मंजूर कर ली गई यानी उसे इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया गया। आदेश 2010-11 से ही प्रभावी कर दिया गया यानी कंपनी को तब से कर छूट हासिल हो गई जब वह वजूद तक में नहीं आई थी और इस बेनिफिट के लिए आवेदन तक नहीं किया था। इस मामले को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच भी चल रही है। आईटी नोटिस के खिलाफ सोनिया और राहुल 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट भी गए लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आईटी नोटिस रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में इनकम टैक्स की जांच चलती रहेगी।

**कर्ज का खेल और एजेएल का अधिग्रहण-** एजेएल पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपये का कर्ज था। कांग्रेस ने इस कर्ज की वसूली का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के मेजॉरिटी शेयर वाली कंपनी YIL को दे दिया। इसके लिए YIL ने 50 लाख रुपये कांग्रेस को दिए और 90 करोड़ रुपये कर्ज की वसूली का अधिकार हासिल कर लिया। कर्ज वसूली

के लिए YIL ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया। सुब्रमण्यन स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने YIL को 90 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली का अधिकार दिया गया और उसके नाम पर YIL ने एजेएल के 2000 करोड़ रुपये से यादा की रियल एस्टेट का अधिग्रहण कर लिया।

**5 लाख की पूंजी से शुरू हुई YIL के पास हो गई 800 करोड़ की संपत्ति-** ईडी के मुताबिक YIL की 2010 में जब स्थापना हुई तब उसका शेयर कैपिटल महज 5 लाख रुपये था। जल्द ही उसे कोलकाता से चलने वाली एक कथित शेल कंपनी से 01 करोड़ रुपये का लोन मिला ताकि ये एजेएल और उसकी सभी संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कांग्रेस के साथ सौदा कर सके। इसी 01 करोड़ रुपये में से ड्घढ्ढरु ने कांग्रेस को 50 लाख रुपये दिए और एजेएल से 90 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली का अधिकार हासिल किया और आखिरकार उसकी सभी संपत्तियों का अधिग्रहण ही कर लिया। ईडी के मुताबिक, 2010 में 5 लाख रुपये की पूंजी से शुरू होने वाली गांधी परिवार के नियंत्रण वाली YIL के पास आज देशभर में 800 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां हैं। इसमें दिल्ली में ITO के नजदीक बहादुर शाह जफर मार्ग पर प्राइम लोकेशन पर स्थित हेराल्ड हाउस भी शामिल है। हेराल्ड हाउस में पासपोर्ट ऑफिस है जिसके लिए सरकार YIL को किराया देती है। इसके अलावा YIL के पास हरियाणा के पंचकूला में 65 करोड़ रुपये मूल्य का प्लॉट है। ये प्लॉट पहले एजेएल के नाम था। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में ईडी ने 3 दिसंबर 2018 को इस संपत्ति को अटैच कर दिया। इसी तरह 2018 में केंद्रीय शहरी और आवास विकास मंत्रालय ने हेराल्ड हाउस का इस आधार पर लीज डीड कैंसल कर दिया कि जिन शर्तों पर 1962 में हेराल्ड हाउस का आवंटन हुआ था, उन शर्तों का पालन नहीं हो रहा। आवंटन मिला था अखबार प्रकाशित करने के लिए लेकिन अखबार का प्रकाशन नहीं हो रहा और संपत्ति को किराये पर देकर कॉमर्शियल फायदा लिया जा रहा है।

करोड़ का कर्ज खत्म करना था। इस 90 करोड़ रुपये में से 67 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन और वीआरएस के लिए दिए गए थे। बाकी सरकार का

बकाया, बिजली के बिल और भवन के लिए भुगतान हुआ। यह अपराध कैसे हो सकता है? नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक आज भी एसोसिएटेड जर्नल्स के पास

है। सारी संपत्ति सुरक्षित है।

**व्या है नेशनल हेराल्ड केस से गांधी परिवार का नाता?**

यह केस नेशनल हेराल्ड अखबार से



जुड़ा है। देश के पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू ने 1938 में इसकी स्थापना की थी। अखबार का मालिकाना हक एजेएल के पास था जो दो और अखबार छपा करती थी। ये थे- हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। 1956 में एजेएल को नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पर बनाया। इसे कंपनी एक्ट की धारा 25 से टैक्स मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे-धीरे घाटे में चली गई। 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया। इस बीच 2010 में यंग इंडियन के नाम से एक अन्य कंपनी बनाई गई। इसके 76 प्रतिशत शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी और बाकी के शेयर मोतीलाल बोरा और आस्कर फर्नांडिस के पास थे। आरोप है कि कांग्रेस ने अपना 90 करोड़ का कर्ज नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ एजेएल ने सारे शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपये एजेएल को दिए। बीजेपी

## नेशनल हेराल्ड केस में अब तक ईडी की कार्रवाई

- ▶▶ 2016 में ईडी ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल बोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ये केस सीबीआई की एक एफआईआर पर आधारित था।
- ▶▶ 2016 में ईडी ने एजेएल को कांग्रेस की तरफ से कथित तौर पर दिए गए 90 करोड़ रुपये कर्ज देने के मामले की जांच शुरू की। जब YIL ने एजेएल का अधिग्रहण किया तो ये कर्ज बाद में माफ कर दिया गया था। इसके बदले में कांग्रेस को YIL से 50 लाख रुपये मिले।
- ▶▶ 3 दिसंबर 2018 को ईडी ने पंचकूला स्थित एजेएल के एक प्लॉट को अटैच कर दिया। उस प्लॉट का बाजार मूल्य 65 करोड़ रुपये था जो एजेएल से जुड़ा था और जिस पर YIL का स्वामित्व था।
- ▶▶ 2022 में ईडी ने यंग इंडियन और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इसके पदाधिकारियों व शेयरहोल्डरों के खिलाफ एक और जांच शुरू की।
- ▶▶ 11-12 अप्रैल 2022 को ईडी ने कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ की।



## इतिहास के नेताओं से सीख लें मोदी जी



एक समय था जब राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते थे पर मनभेद नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बीच भी तल्लखी खूब थी लेकिन नेहरू जी ने अपने शासन में उन्हें कश्मीर के मामले में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। वहीं नेहरू जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच कुछ ठीक नहीं था लेकिन नेहरू ने उन्हें कानून मंत्री बनाया। नेहरू ने विपक्षी दल में होने के बावजूद अटल जी को हर जगह सराहा। देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विदेश में भारत का पक्ष रखने भेजा करते थे। ऐसा ही सम्मान स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी इंदिरा गांधी की तरफ दिखाया करते थे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में अटलजी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा की उपमा दी थी। अटल जी ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा भी मर्यादा के साथ उठाया था। लोहिया जी और जवाहरलाल नेहरू की आपस में कभी नहीं पटती थी पर

जवाहरलाल नेहरू और लोहिया जी के बीच पूरा आदर भाव था। नेहरू जी की आखरी दर्शन यात्रा में किसी के जूते पहन कर ऊपर चढ़ जाने से उस व्यक्ति को लोहिया जी ने सरेआम लताड़ा। यही आपसी आदरभाव जेपी और इंदिरा गांधी के बीच था।

नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यंग इंडियन प्राइवेट ने सिर्फ 50 लाख रुपये में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला जो नियमों के खिलाफ है।

### ईडी के रडार पर कौन-कौन आया?

नैशनल हेराल्ड केस में ही ईडी ने अप्रैल 2022 में कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेजा था। उनसे कई घंटे पूछताछ भी हुई। इसी केस में कांग्रेस के पवन बंसल भी ईडी दफ्तर बुलवाए गए। खड़गे और बंसल, दोनों ही एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) में पदाधिकारी हैं जो नैशनल हेराल्ड का प्रकाशन करती है। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटैल के खिलाफ स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जांच की थी। महाराष्ट्र के



कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फरवरी 2022 में मलिक की कई संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। मलिक पर अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते होने का भी आरोप है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी एक्शन ले चुका है। ईडी महाराष्ट्र के डेप्युटी सीएम अजीत पवार के खिलाफ रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी ईडी केस चला रहा है। पूर्व पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह को फरवरी में अरेस्ट किया गया था। ईडी ने अप्रैल में चन्नी का बयान भी दर्ज किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम, डीके शिवकुमार को भी ईडी के मुकदमों के चलते महीनों न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। पात्रा चॉल घोटाला मामले में ईडी ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ भी कार्रवाई की थी और वर्तमान में भी उन्हें तलब किया है। बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनम नाइक के खिलाफ भी ईडी केस चल रहा है।

## लोकतंत्र के लिए खतरनाक है निचले स्तर की राजनीति

मोदी सरकार में राजनीति अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। बदजुबानी और आपसी वैमनस्य की शुरुआत तो वैसे 2014 से ही शुरू हो गई थी, जब केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। यही कारण है कि आज अपने राजनैतिक विरोधियों को कुचलना और इस वैमनस्यता वाली राजनैतिक सोच ने लोकतंत्र को अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया। कहा जा सकता है कि पिछले आठ साल में एक सोची समझी साजिश के तहत मोदी सरकार ने विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची है। इस साजिश में विपक्ष के नेताओं पर कानूनी तरीके से परेशान करना, बदले की भावना से नेताओं के साथ व्यवहार करना, कई विपक्षी कददावर नेताओं के विषय में अपशब्दों का उपयोग करना (जैसे राहुल गांधी को पप्पू कहना) और विपक्ष के नेताओं को सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं की कार्रवाई करवाने की धमकी देकर अपने पाले में करने की साजिश रचना प्रमुख हैं। मोदी सरकार के यह ऐसे षडयंत्र हैं जिनके डर से कई नेता या तो बीजेपी में शामिल हो गये या अपने आप को चुप करके शांत बैठ गये। इसका परिणाम यह हुआ कि आज विपक्ष कमजोर हो गया और मोदी सरकार अपनी हिटलरशाही पर उतर आयी। मोदी सरकार का यह रवैया देश के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब-जब देश में विपक्ष कमजोर हुआ है तब-तब देश खतरे में पड़ा है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच ईडी कर रहा है। तमिलनाडु में टीटीवी दिनाकरण, जम्मू कश्मीर किट एसोसिएशन में कथित घोटाले से जुड़े केस

में पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला भी ईडी के रडार पर रहे। केरल गोल्ड स्कैम मामले में सीएन पिनाराई विजयन से लेकर लेफ्ट के कई नेता और सरकारी अधिकारी ईडी के निशाने पर हैं।

### ईडी का क्यों होता है इस्तेमाल?

प्रवर्तन निदेशालय देश की इकलौती ऐसी केंद्रीय एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों के लिए राजनेताओं या सरकारी अधिकारियों को तलब करने की खातिर सरकार की हरी झंडी की जरूरत नहीं पड़ती। नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) का काम आतंक से जुड़े अपराधों तक सीमित है। सीबीआई को राज्य सरकारों से इजाजत लेनी पड़ती है। हालांकि, ईडी के एक्शन की टाइमिंग पर खूब सवाल उठते हैं। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि ईडी या सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां महत्वपूर्ण चुनावों से पहले विपक्षी नेताओं को निशाना बनाती हैं।





राष्ट्रपति चुनाव....



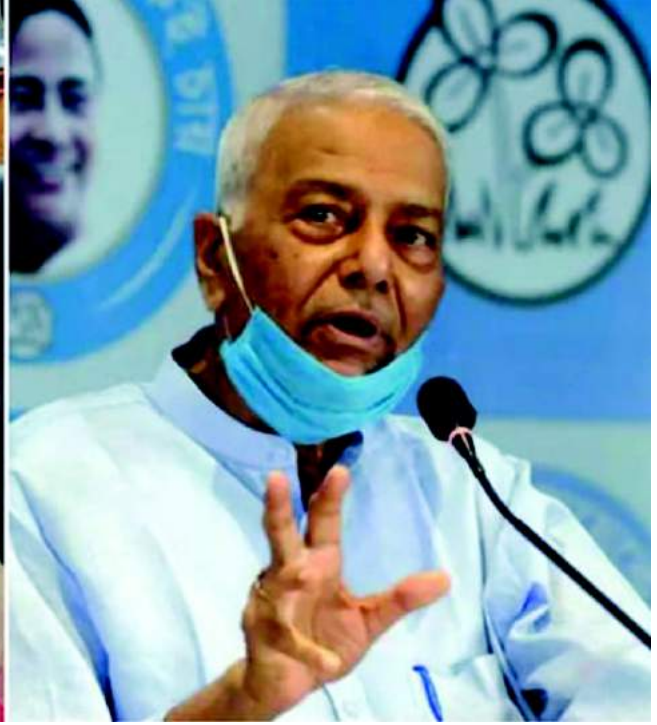
# रबर स्टॉप बनकर न रहे राष्ट्रपति का पद

## शैफाली रुबे/अर्चना शर्मा

राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद ही अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी है। 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को काउंटिंग का ऐलान होते ही नेताओं के घरों की फोन की घंटियां बजने लगीं और मंथन शुरू हो गया। सत्तारूढ़ भाजपा की अगुआई वाले एनडीए के पास

कुल 10.79 लाख वोटों के आधे से थोड़ा कम यानी 5,26,420 है। विपक्ष की तुलना में भाजपा की स्थिति मजबूत है। देश के नए राष्ट्रपति को चुनने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। देश के 776 सांसद और 4,033 विधायक मिलकर 25 जुलाई से पहले देश

का नए राष्ट्रपति चुन लेंगे। इसके लिए अब शह-मात का खेल शुरू हो चुका है। दोनों खेमे इस चुनाव को सिर्फ राष्ट्रपति चुनने तक ही नहीं बल्कि माइंड गेम के लिए अवसर मान रहे हैं। दोनों खेमों को लगता है कि इस चुनाव में 2024 आम चुनाव के सियासी समीकरण का भी संकेत मिलेगा। यही वजह है कि दोनों ओर से बिसात



बिछाने का काम शुरू हो गया है। इस साल की शुरुआत से ही भाजपा विभिन्न चुनाव में विपक्ष पर भारी पड़ी है। इसका असर राष्ट्रपति चुनाव पर भी दिख सकता है। भाजपा को उन दलों का भी समर्थन मिल सकता है जो उससे दूर थे। साथ ही विपक्षी खेमे में भी संध लग सकती है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने जहां यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू मैदान में हैं। सपा-शिवसेना जैसे मजबूत क्षेत्रीय दलों के दरकर रहे गढ़ों के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी अब झटका लगा है। इसका आने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव पर भी इन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ सकता है। तीन लोकसभा और सात विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा ने दो लोकसभा और तीन विधानसभा चुनाव जीतने में सफलता हासिल की है। इससे विपक्षी एकता पर यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है। इसके साथ ही चलंत मुद्दों पर मोदी सरकार की लोकप्रियता भारी

पड़ती दिखाई दी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी भाजपा ने जमीन मजबूत कर ली है। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी इन सब का काफी असर पड़ सकता है।

मौजूदा गुणा-गणित के लिहाज से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा उनको चुनौती देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये संयोग ही है कि दोनों का झारखंड कनेक्शन है। द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रह चुकी हैं तो यशवंत सिन्हा का राजनीतिक करियर झारखंड में ही रहा है। मगर दोनों का फैमिली बैकग्राउंड अलग-अलग है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जमाने में यशवंत सिन्हा पर द्रौपदी मुर्मू भारी पड़ती दिख रही है। यशवंत सिन्हा की पत्नी नीलिमा सिन्हा को भी अपनी पति की जीत पर भरोसा नहीं है।

### नंबर गेम समझिए

भाजपा की सीटें लोकसभा में काफी

बढ़ी हैं, हालांकि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल बदला है और कई राज्यों की विधानसभाओं में स्थिति कमजोर हुई है, जिस कारण भगवा दल को क्षेत्रीय पार्टियों का सहारा लेना होगा। हालांकि विपक्ष की तुलना में एनडीए बेहतर स्थिति में है और उसके पास बढ़त है।

### वोटों की गुणा-गणित में विपक्ष से एनडीए आगे

राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गुणा-गणित देखें तो सत्तारूढ़ भाजपा की अगुआई वाले एनडीए के पास कुल 10.79 लाख वोटों के आधे से थोड़ा कम यानी 5,26,420 है। इसी साल अप्रैल में उच्च सदन में 100 के आंकड़े पर पहुंचने वाली भाजपा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा की 57 सीटों के लिए हाल में हुए द्विवार्षिक चुनावों के बाद 95 से घटकर 91 पर आ गई। 57 सदस्यों को मिलाकर वर्तमान में उच्च सदन के कुल 232 सदस्यों में भाजपा के 95 सदस्य हैं। उसे वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल के सहयोग की





दरकार थी। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी ने खाई को पाट दिया। एनडीए को करीब 13,000 वोट कम पड़ रहे थे। अकेले बीजेडी के पास 31 हजार से यादा वोट हैं और YSRCP के पास 43,000 से ज्यादा। बीजू जनता दल ने सपोर्ट का एलान कर दिया है। विपक्ष की तुलना में भाजपा की स्थिति मजबूत है। दरअसल, हाल के वर्षों में शिवसेना और अकाली दल के साथ भाजपा के रास्ते अलग हो गए। वहीं, AIADMK के सदस्य तमिलनाडु विधानसभा में घटे हैं। भाजपा ने यूपी चुनाव में फिर से सत्ता हासिल तो कर ली लेकिन उसकी संख्या घटी है। उसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तुलनात्मक रूप से भी नुकसान हुआ है। हालांकि विपक्ष की तुलना में एनडीए बेहतर स्थिति में है और उसके पास बढ़त है।

### राज्यसभा में भाजपा की पावर घटी!

इसी साल अप्रैल में उच्च सदन में 100

के आंकड़े पर पहुंचने वाली भाजपा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा की 57 सीटों के लिए हाल में हुए द्विवार्षिक चुनावों के बाद 95 से घटकर 91 पर आ गई। 57 सदस्यों को मिलाकर वर्तमान में उच्च सदन के कुल 232 सदस्यों में भाजपा के 95 सदस्य हैं। सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों में भाजपा के 26 सदस्य शामिल हैं जबकि इस द्विवार्षिक चुनाव में उसके 22 सदस्यों ने जीत दर्ज की। इस प्रकार उसे चार सीटों का नुकसान हुआ है। निर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने के बाद भाजपा के सदस्यों की संख्या 95 से घटकर 91 रह जाएगी। यानी फिर से 100 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए भाजपा को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

### भाजपा की स्थिति मजबूत

अब हम बात करते हैं सांसदों के वोट वेटेज की। देश में 543 लोकसभा सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में 245 सांसद हैं। इसमें

से 13 राज्यसभा सांसद मनोनीत हैं तो वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। उदाहरण के तौर पर आप यूपी को ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सांसद हैं। यहां सबसे ज्यादा बीजेपी के 62 सांसद हैं। जबकि राज्य में एक सांसद के वोट का वेटेज 700 है। ऐसे में बीजेपी सांसदों के वोट का कुल वेटेज 43,400 है। जबकि बीजेपी गठबंधन की एक अन्य पार्टी अपना दल के दो सांसद हैं। अपना दल के इन दो सांसदों के वोट का वेटेज 1400 हो जाता है। वहीं बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सांसद बसपा के हैं। राज्य में बसपा के दस सांसद हैं, जिनके वोट का वेटेज 7,000 है। इसके अलावा सपा के पांच सांसदों के वोट का वेटेज 3,500 है। वहीं कांग्रेस के एक मात्र सांसद होने के कारण उसके पास 700 वोट का वेटेज है।



## नूपुर शर्मा : बयान से बर्खास्तगी तक

### जगत विजन संवाददाता

भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादास्पद बयान के बाद से देश भर के कई राज्यों में हंगामा रुक नहीं रहा। नूपुर के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को रोकने के लिए प्रशासन कवायद में लगी है। देश के कई राज्यों में नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर हुई है। और मांग की जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी की जाये। एक समुदाय बयान की काफी निंदा कर रहा

है। दरअसल 28 मई 2022 को टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की गई थी। उनके आपत्तिजनक बयान के बाद मामला तूल पकड़ने लगा था। नूपुर शर्मा के खिलाफ कुछ राज्यों में मामले दर्ज किए गए और गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। यूपी के कानपुर में जो हिंसा भड़की उसके पीछे इसी को कारण बताया जा रहा है। नूपुर शर्मा के बयान का असर अरब देशों में

भी शुरू हो गया था। कुवैत, दुबई, सऊदी अरब इन जगहों पर विरोध शुरू था। सउदी अरब, कुवैत, बहरीन के सुपर स्टोर से भारतीय सामान हटा दिया गया था और भारतीय सामान के बहिष्कार को लेकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। अपने नेताओं के धार्मिक, भड़काऊ बयानों से बीजेपी ने किनारा किया। नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद बयान के बाद खाड़ी और मुस्लिम देशों ने भारत से नाराजगी जताई



## पैगंबर विवाद में अब तक क्या-क्या हुआ?

- ▶▶ बीजेपी से सस्पेंड नूपुर शर्मा के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मुंबई पुलिस जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए समन भेज सकती है।
- ▶▶ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। बोर्ड की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई है जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेताओं को पार्टी से सिर्फ निलंबित करने ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कड़ी सजा की मांग की है।
- ▶▶ ओमान, इंडोनेशिया, इराक, मालदीव, जॉर्डन, लीबिया और बहरीन इस्लामिक दुनिया के उन देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पैगंबर के खिलाफ बीजेपी नेताओं की टिप्पणी की निंदा की है। पैगंबर मोहम्मद विवाद में कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत कई देशों ने पहले ही विरोध जताया था। इस सूची में करीब 15 देश भारत से अपना विरोध जता चुके हैं।
- ▶▶ कुवैत के डिपार्टमेंटल स्टोर पर भारतीय उत्पादों के खिलाफ एक नोटिस लगाया गया है। इस नोटिस का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं एक दूसरे वीडियो में भारतीय उत्पादों को स्टोर से हटाया जा रहा है।
- ▶▶ 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। इस्लामिक सहयोग संगठन के सचिवालय ने पैगंबर के खिलाफ बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों का हवाला देते हुए भारत में मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने की कोशिशों का नाम देने का प्रयास किया।
- ▶▶ इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना के बाद विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजेपी के नेताओं की टिप्पणियां किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।
- ▶▶ भारतीय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ओआईसी की ओर से निंदा के बाद साफ किया कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को विदेश मंत्रालय ने गैर जरूरी करार दिया।
- ▶▶ बीजेपी से सस्पेंड नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए मिल रही धमकियों के लिए नूपुर की शिकायतों पर दिल्ली पुलिस ने स्नद्व दर्ज कर अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
- ▶▶ नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर माफी मांग ली थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। हमारे महादेव के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ चीजें कह दीं। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापिस लेती हूँ।
- ▶▶ पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी पहले ही नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। नूपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से निकाला गया है। नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा फैसला हुआ जिसमें पार्टी के दो प्रवक्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया गया। बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया वहीं दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया। नूपुर शर्मा की गिनती पार्टी के तेज-तरार प्रवक्ताओं में होती है और कल तक मीडिया के सामने पार्टी का स्टैंड मजबूती से रखती थीं। पार्टी के दो नेताओं पर जो कार्रवाई हुई उससे कुछ घंटे पहले बीजेपी ने एक बयान जारी कर कहा है कि पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। पार्टी किसी भी धर्म से जुड़े व्यक्तित्व के आलोचना की कड़ी निंदा करती है। पार्टी ने इस संदर्भ में नूपुर शर्मा का सीधे-सीधे जिक्र नहीं किया था। पार्टी की ओर से कहा गया कि भारत ने हजारों साल के इतिहास में हर धर्म फलाफूला है। बीजेपी ऐसी किसी भी विचारधारा के खिलाफ है, जो किसी भी वर्ग या धर्म का अपमान या उसे बदनाम करती है। पार्टी ऐसे लोगों और दर्शन को बढ़ावा नहीं देती है।

पैगंबर पर विवादित टिप्पणी पर नूपुर शर्मा ने माफी भी मांगी। नूपुर ने कहा- किसी को कष्ट पहुंचाने का मकसद नहीं, अपने शब्द वापस लेती हूँ। हालांकि इसके बाद भी देश में यह मामला शांत नहीं हुआ। बयान पर नूपुर की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। इस बयान के बाद से ही देश के अंदर एक दहशत का माहौल बन गया है।

# OMICRON

## क्या फिर डराने लगा है कोरोना?

### नए वेरिएंट्स ओमीक्रोन बन रहा खतरा

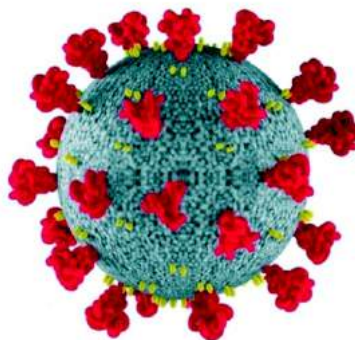
**कुमार नवीन**

ओमीक्रोन ने पिछले साल पूरी दुनिया में खूब कहर बरपाया। भारत में भी ज्यादातर कोविड मरीजों में यही वेरिएंट मिल रहा है। मगर अब इसके सबवेरिएंट्स चिंताजनक रफ्तार से फैलने लगे हैं। ओमीक्रोन का सबवेरिएंट BA.2.12.1 भारत पहुंच गया है। हालांकि अभी इसका इन्फेक्शन सीमित है मगर राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ओमीक्रोन के सबवेरिएंट्स BA.4 और BA.5 के कई मामले मिले हैं। BA.5 की मौजूदगी 47 देशों में है जबकि BA.2 42 देशों में सामने आया है। राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक नए सबवेरिएंट्स के जितने मामले मिले हैं, सब मरीज

रिकवर हो चुके हैं। फिर भी हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सचेत करते हुए कहा कि ओमीक्रोन से संमित हो चुके लोगों को नए वेरिएंट्स से ज्यादा खतरा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, सबवेरिएंट्स की वजह से मामलों

में बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। अगर बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग हुई केसेज में स्पाइक देखने को मिल सकता है।

**कहां तेजी से फैल रहा है कोरोना नए वेरिएंट जिम्मेदार-** कोविड-19 मामले और साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर को देखें तो 12 से ज्यादा शहरों में पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से ज्यादा है। मुंबई सिटी का वीकली पॉजिटिविटी रेट (WPR) 15.6 प्रतिशत हो गया है। ठाणे में कोविड के नए मामलों में 3.2 गुना और और पुणे में 2.2 गुना बढ़त दर्ज की गई है। केरल के छह जिलों में संमण चिंताजनक रफ्तार से फैल रहा है। एर्नाकुलम का WPR 17.8 प्रतिशत है, कोट्टायम का 17.4 प्रतिशत और कोझिकोड का 15.9 प्रतिशत जो देश





में सबसे ज्यादा है। कर्नाटक के बंगलुरु शहरी और हरियाणा के गुरुग्राम में भी एक्टिव केस तेजी से बढ़े हैं। एक्टिव केसेज की बात करें तो महाराष्ट्र में देश के 32 प्रतिशत सक्रिय मामले हैं। केरल की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत है। नैशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉ. सुजीत सिंह के अनुसार, सिर्फ नए वेरिएंट्स की वजह से ही केसेज में उछाल नहीं है। उन्होंने कहा कि ताजा बढ़त के पीछे कई फैक्टर्स हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय आबादी की इम्युनिटी अलग-अलग स्टेज में है, ऐसे में उन्हें संक्रमण का खतरा बना रहेगा। डॉक्टर ने कहा कि सांस के संक्रमण में मामले कभी जीरो नहीं हो सकते। डॉ. सिंह ने कहा कि ओमीक्रोन भारत का सबसे प्रमुख वेरिएंट है। ओमीक्रोन के प्रभुत्व का अंदाजा इस बात से लगाएं कि मुंबई की 12वीं जीनोम स्टडी में 99.5 प्रतिशत सैम्पल्स इसी के थे। केवल एक सैम्पल डेल्टा वेरिएंट का मिला।

**नए वेरिएंट्स पर राज्यों और केंद्र से क्या अपडेट है?**- मुंबई में अधिकारियों ने ओमीक्रोन के BA.4 और BA.5 सबवेरिएंट्स की पुष्टि की। सूत्रों के अनुसार, पुणे व कुछ अन्य जिलों में BA.2.12.1 के केस भी मिले हैं। महाराष्ट्र में अब इन वेरिएंट्स के 15 मामले हो चुके हैं। मुंबई के अलावा पुणे और ठाणे में भी कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं। मुंबई का वीकली पॉजिटिविटी रेट 15 प्रतिशत से ज्यादा है। तमिलनाडु में 19 साल का एक युवक BA.4 वेरिएंट से संमित मिला है।

**नए वेरिएंट्स पर केंद्र ने क्या कहा?**- केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि BA.2.12.1 (BA.2 का सबवेरिएंट, दोनों ओमीक्रोन से निकले), BA.4 और BA.5 के मामले दुनियाभर में बढ़ रहे हैं। देश में भी इनके केस मिले हैं। केंद्र ने नोट में कहा कि BA.2.12.1 नॉर्थ अमेरिका में

## क्या भारत में कोविड की चौथी लहर आ रही है?

क्या कुछ महीनों की राहत के बाद भारत कोविड की चौथी लहर की तरफ बढ़ रहा है? आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। अब घबराने की जरूरत नहीं है। एस-आई-आर मॉडल के ज़रिए कोविड की पिछली तीन लहरों में सटीक आंकलन कर चुके प्रोफेसर रंजन ने कहा, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले अचानक दिल्ली में केस बढ़ने लगे थे। यह इजाफा लोकल ही था। महाराष्ट्र और केरल में कुल मिलाकर रोज़ाना 8-9 हजार केस आ रहे हैं। यह राज्यवार एक छोटी लहर जैसा मामला है। संभव है कि महीने के अंत तक प्रतिदिन 30 से 50 हजार केस आ जाएं, लेकिन नैशनल लेवल पर एक साथ केस बढ़ना या पीक आने जैसा कुछ नहीं होगा। अपनी बात समझाते हुए प्रोफेसर रंजन कहते हैं, अगले एक साल तक ऐसा हो सकता है कि कभी एक राज्य तो कभी दूसरे राज्य में केस बढ़ें। इस बार महाराष्ट्र है, तो अगली बार पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश हो सकता है, लेकिन एक बात से बेफि रहें कि दूसरी वेव में हुई त्रासदी जैसा कुछ हो सकता है। इन्फेक्शन हल्का होगा। महाराष्ट्र और केरल में नए केसों में तेजी की वजह वहां आबादी का घनत्व है। उत्तर प्रदेश और बिहार में केस बढ़े तो पीक छोटा ही होगा। ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए प्रोफेसर रंजन ने बताया, वहां भी सारी पाबंदियां हटा लेने के बाद केस कुछ बढ़े थे, लेकिन अब स्थितियां ठीक हैं। पहली तीन लहरों में नियमों का पालन करने वाले लोग साधारण जीवन में लौट आए हैं। वे अब मास्क नहीं लगाते। पार्टियां और समारोह में भी होने लगे हैं। ऐसे में लोकल स्तर पर साधारण सर्दी-जुकाम जैसे लक्षणों वाले केस बढ़ सकते हैं। जो तीनों लहरों में कोविड संक्रमण से बचे रहे, वे इसका शिकार हो सकते हैं।

उछाल की वजह है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी कुछ मामलों की पहचान हुई है।

**दिल्ली के चार जिले दे रहे टैशन-** दिल्ली में चार जिलों का पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है। साउथ, ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अब ऑरेंज जोन में आ गए हैं। दिल्ली की बात करें तो

औसत वीकली पॉजिटिविटी रेट 3.79 प्रतिशत तक पहुंच गया है जो जून के पहले हफ्ते में 2.17 प्रतिशत था। दिल्ली में संगम दर में कमी तो जरूर दर्ज हुई है, लेकिन एक दिन में नए मरीजों की संख्या एक हजार से अधिक हो गई है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हजार के पार 3177 तक पहुंच गई।

# न्यायालयों में राजस्व मामलों का बोझ



## प्रमोद भार्गव

ऐसा पहली बार देखने में आया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने न्यायालयों में बढ़ते मामलों के मूल कारण में जजों की कमी के साथ राजस्व न्यायालयों को भी दोषी ठहराया है। रमणा ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों और क्षेत्राधिकार के विभाजन की संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि कर्तव्यों का पालन करते समय हम सभी को लक्ष्मण रेखा की मर्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो न्यायपालिका कभी भी शासन के रास्ते में आड़े नहीं आएगी। आज जो न्यायपालिका में मुकदमों का ढेर लगा है, उसके लिए जिम्मेदार प्रमुख प्राधिकरणों

द्वारा अपना काम ठीक से नहीं करना है। इसलिए सबसे बड़ी मुकादमेबाज सरकार हैं। न्यायालयों में 66 प्रतिशत मामले राजस्व विभाग से संबंधित हैं। राजस्व न्यायालय एक तो भूमि संबंधी प्रकारणों का निराकरण नहीं करती हैं, दूसरे न्यायालय निराकरण कर भी देती है तो उस पर वशों अमल नहीं होता है। नतीजतन अवमानना के मुकादमे बढ़ने की भी एक नई श्रेणी तैयार हो रही है। अदालत का आदेश होने के बावजूद उसका यिान्वयन नहीं करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। रमणा ने मामलों का बोझ बढ़ने का कारण गिनाते हुए का कि तहसीलदार यदि भूमि के नामांतरण और बंटवारे समय पर कर दें तो किसान अदालत क्यों जाएगा? यदि नगर

निगम, नगरपालिकाएं और ग्राम पंचायत ठीक से अपना काम करें तो नागरिक न्यायालय का रुख क्यों करेगा? यदि राजस्व विभाग परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण विधि सम्मत करे तो लोग अदालत के दरवाजे पर दस्तक क्यों देंगे? ऐसे मामलों की संख्या 66 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि जब हम सब संवैधानिक पदाधिकारी हैं और इस व्यवस्था का पालन करने के लिए जिम्मेदार है और हमारे क्षेत्राधिकार भी स्पष्ट हैं, तब समन्वय के साथ दायित्व पालन करते हुए राष्ट्र की लोकतांत्रिक नींव मजबूत करने की जरूरत है। रमणा ने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आहूत मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के



सम्मेलन में कही है।

अदालतों में मुकादमों की संख्या बढ़ाने में राज्य सरकारें निश्चित रूप से जिम्मेवार हैं। वेतन विसंगतियों को लेकर एक ही प्रकृति के कई मामले ऊपर की अदालतों में विचाराधीन हैं। इनमें से अनेक तो ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें सरकारें आदर्श व पारदर्शी नियोक्ता की शर्तें पूरी नहीं करती हैं। नतीजतन जो वास्तविक हकदार हैं, उन्हें अदालत की शरण में जाना पड़ता है। कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी बकाए के भुगतान के लिए अदालतों में जाते हैं। जबकि इन मामलों को कार्यपालिका अपने स्तर पर निपटा सकती है। हालांकि कर्मचारियों से जुड़े मामलों का सीधा संबंध विचाराधीन कैदियों की तदाद बढ़ाने से नहीं है, लेकिन अदालतों में प्रकरणों की संख्या और काम का बोझ बढ़ाने का काम तो ये मामले करते ही हैं। इसी तरह पंचायत पदाधिकारियों और राजस्व मामलों का निराकरण राजस्व न्यायालयों में न होने के



कारण न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और बिजली बिलों का विभाग स्तर पर नहीं निपटना भी अदालतों पर बोझ बढ़ा रहे हैं। कई प्रांतों के भू-राजस्व कानून विसंगतिपूर्ण हैं। इनमें नाजायज कब्जे को वैध ठहराने के

उपाय हैं। जबकि जिस व्यक्ति के पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं, वह भटकता रहता है। इन विसंगतिपूर्ण धाराओं का विलोपीकरण करके अवैध कब्जों से संबंधित मामलों से निजात पाई जा सकती है। लेकिन नौकरशाही ऐसे कानूनों का वजूद बने रहना





चाहती है, क्योंकि इनके बने रहने पर ही इनके रौब-रुतबा और पौ-बारह सुनिश्चित हैं।

हमारे यहां संख्या के आदर्श अनुपात में कर्मचारियों की कमी का रोग अक्सर रोया जाता है। ऐसा केवल अदालत में हो, ऐसा नहीं है। पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध न कराने का यही बहाना है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों एवं उनके सहायक कर्मचारियों की कमी बड़ी संख्या में देखने में आई थी। इसकी पूर्ति आउट सोर्स के माध्यम से चिकित्सक एवं कर्मचारी तैनात करके तत्काल तो कर ली गई थी, किंतु कोरोना संकट के खत्म होते ही उन्हें हटा दिया गया। नतीजतन कमी यथावत है। जजों की कमी कोई भी नई बात

नहीं है, 1987 में विधि आयोग ने हर 10 लाख की आबादी पर जजों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 करने की सिफारिश की थी। फिलहाल यह संख्या 17 कर दी गई है। जबकि विष्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा आस्ट्रेलिया में 58, कनाडा में 75, फ्रांस में 80 और ब्रिटेन में 100 है। हमारे यहां जिला एवं सत्र न्यायालय में 21 हजार की तुलना में 40 हजार न्यायाधीशों की जरूरत है। मार्च 2016 तक देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल 1056 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 434 पद खाली हैं। हालांकि हमारे यहां अभी भी 14,000 अदालतों में 17,945 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। अदालतों का संस्थागत ढांचा भी बढ़ाया गया है। उपभोक्ता, परिवार और किशोर न्यायालय अलग से अस्तित्व

में आ गए हैं। फिर भी काम संतोशजनक नहीं हैं। उपभोक्ता अदालतें अपनी कार्य संस्कृति के चलते अब बोझ साबित होने लगी हैं। बावजूद औद्योगिक घरानों के वादियों के लिए पृथक से वाणिज्य न्यायालय बनाने की पैरवी की जा रही है।

अलबत्ता आज भी ब्रिटिश परंपरा के अनुसार अनेक न्यायाधीश ग्रीष्म ऋतु में छुट्टियों पर चले जाते हैं। सरकारी नौकरियों में जब से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हुआ है, तब से हरेक विभाग में महिलाकर्मियों की संख्या बढ़ी है। इन महिलाओं को 26 माह के प्रसूति अवकाश के साथ दो बच्चों की 18 साल की उम्र तक के लिए दो वर्ष का बाल सुरक्षा अवकाश भी दिया जाता है। अदालत से लेकर अन्य सरकारी विभागों में मामलों के





लंबित होने में ये अवकाश एक बड़ा कारण बन रहे हैं। इधर कुछ समय से लोगों के मन में यह भ्रम भी पैठ कर गया है कि न्यायपालिका से डंडा चलवाकर विधायिका और कार्यपालिका से छोटे से छोटा काम भी कराया जा सकता है। इस कारण न्यायलयों में जनहित याचिकाएं बढ़ रही हैं, जो न्यायालय के बुनियादी कामों को प्रभावित कर रही हैं। जबकि प्रदूषण, यातायात, पर्यावरण और पानी जैसे मुद्दों पर अदालतों के दखल के बावजूद इन क्षेत्रों में बेहतर स्थिति नहीं बनी है। सरकारी नौकरी में आर्थिक सुरक्षा और प्रतिष्ठा निर्मित हो जाने से बौद्धिक योग्यता और पद प्रतिष्ठा की एक नई संस्कृति पनपी है। यदि कोई युवक या युवती सिविल जज बन जाता है, तो वे सिविज जज से ही शादी करने लग गए हैं। शादी के बाद दर्पित की अलग-अलग जगह पदस्थापना इन्हें मिलने में रोड़ा बनती है, अतएव ये लोग किसी न किसी बहाने छुट्टी लेकर एक-दूसरे से मिलने चले जाते हैं। ये नई संस्कृति अदालतों में काम का बोझ बढ़ाने का नया कारण बन गई है।

न्यायिक सिद्धांत का तकाजा तो यही है

कि एक तो सजा मिलने से पहले किसी को अपराधी न माना जाए, दूसरे आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति का फेसला एक तय समय-सीमा में हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहां ऐसा संभव नहीं हो पाता। इसकी एक वजह न्यायालय और न्यायाधीशों की कमी जरूर है, लेकिन यह आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। मुकदमों को लंबा खिंचने की एक वजह अदालतों की कार्य-संस्कृति भी है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजेंद्रमल लोढ़ा ने कहा भी था न्यायाधीश भले ही निर्धारित दिन ही काम करें, लेकिन यदि वे कभी छुट्टी पर जाएं तो पूर्व सूचना अवश्य दें। ताकि उनकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। इस तथ्य से यह बात सिद्ध होती है कि सभी अदालतों के न्यायाधीश बिना किसी पूर्व सूचना के आकस्मिक अवकाश पर चले जाते हैं। गोया, मामले की तारीख आगे बढ़ानी पड़ती है। इन्हीं न्यायमूर्तियों ने कहा था कि जब अस्पताल 365 दिन चल सकते हैं तो अदालतें क्यों नहीं? यह बेहद सटीक सवाल था। हमारे यहां अस्पताल ही नहीं, राजस्व और पुलिस विभाग के लोग भी

लगभग 365 दिन ही काम करते हैं। किसी आपदा के समय इनका काम और बढ़ जाता है। इनके कामों में विधायिका और खबरपालिका के साथ समाज का दबाव भी रहता है। बावजूद ये लोग दिन-रात कानून के पालन के प्रति सजग रहते हैं। जबकि अदालतों पर कोई अप्रत्यक्ष दबाव नहीं होता है।

यही प्रकृति वकीलों में भी देखने में आती है। हालांकि वकील अपने कनिष्ठ वकील से अकसर इस कमी की वैकल्पिक पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन वकील जब प्रकरण का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाते अथवा मामले को मजबूती देने के लिए किसी दस्तावेजी साक्ष्य को तलाश रहे होते हैं तो वे बिना किसी ठोस कारण के तारीख आगे खिसकाने की अर्जी लगा देते हैं। विडंबना है कि बिना कोई ठोस पड़ताल किए न्यायाधीश इसे स्वीकार भी कर लेते हैं। तारीख बढ़ने का आधार बेवजह की हड़तालें और न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं के परिजनों की मौंते भी हैं। ऐसे में श्रद्धांजली सभा कर अदालतें कामकाज को स्थगित कर देती हैं। न्यायमूर्ति लोढ़ा ने इस तरह के स्थगन और हड़तालों से बचने की सलाह दी थी। लेकिन जिनका स्वार्थ मुकदमों को लंबा चलाने में अंतर्निहित है, वहां ऐसी नसीहतें व्यार्थ हैं? लिहाजा कड़ाई बरतते हुए कठोर नियम बनाने की जरूरत है। अगली तारीख का अधिकतम अंतराल 15 दिन से ज्यादा का न हो, दूसरे अगर किसी मामले का निराकरण समय-सीमा में नहीं हो पा रहा है तो ऐसे मामलों को विशेष प्रकरण की श्रेणी में लाकर उसका निराकरण त्वरित और लगातार सुनवाई की प्रक्रिया के अंतर्गत हो। ऐसा होता है, तो मामलों को निपटाने में तेजी आ सकती है। बहरहाल प्रधान न्यायाधीश ने जो खरी-खरी बातें कहीं हैं, उन पर राजस्व अदालतों को अमल करने की जरूरत है।

# आधिक कार्बन उत्सर्जन पर कड़ाई जरूरी

## शब्बीर कादरी

जलवायु परिवर्तन इन दिनों गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में ज्वलंत मुद्दा बनकर विश्व के सभी देशों को चेता रहा है कि प्रकृति के संतुलन से छेड़छाड़ मानव द्वारा यदि, अब भी नहीं रोकी गई तो इस ग्रह से जीवन का लुप्त होना सुनिश्चित है। इसी तथ्य को सामने रखकर आज संसार के प्रमुख वैज्ञानिक और देश इस ग्रह और उसमें विद्यमान जीवन को बचाने की चिंता कर रहे हैं, जैसे-जैसे विकास चक्र पर जीवन आगे बढ़ता जाता है पर्यावरणीय परिस्थितियां और अधिक संकटमय बनती जाती हैं। बढ़ते तापमान से पूरी दुनिया में त्राहि-त्राहि है। याद रहे पृथ्वी का औसत तापमान 18वीं शताब्दी के बाद से अब तक 0.6 डिग्री सेन्टीग्रेड तक

बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का मत है कि यदि तापमान वृद्धि की यही रफ्तार रही तो वर्ष 2100 तक यह 1.4 से 5.8 डिग्री सेन्टी. तक बढ़ जाएगा जो पिछले 10,000 वर्षों में किसी सदी में बढ़ा सबसे अधिक तापमान होगा। समुद्र का स्तर बीसवीं शताब्दी में औसतन 10 से 20 सें.मी. बढ़ चुका है और वर्ष 2100 तक इस स्तर के 9.58 से.मी. और बढ़ जाने की संभावना है। 2001 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन पर अन्तर सरकार पैनल की तीसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके पुख्ता प्रमाण है कि पिछले 20 वर्षों में तापमान केवल मानव गतिविधियों के कारण ही बढ़ा है। अतः सहज ही समझा जा सकता है कि पृथ्वी पर सन्निकट पर्यावरणीय संकट के लिए अगर कोई दोषी है तो वह केवल

मानव ही है।

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अपने पहले भाषण में वान की मून ने कहा था, पर्यावरण में बदलाव भविष्य में युद्ध और संघर्ष की बड़ी वजहें बन सकते हैं। महासचिव ने विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस छोड़ने वाले अमेरिका से अपील की कि वह ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करे। श्री मून का मत है कि युद्ध में मानवता को जितना नुकसान होता है उतना ही जलवायु संकट और ग्लोबल वार्मिंग से होना है, उनके अनुसार अफ्रीका और छोटे द्वीपों पर रह रहे लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे अधिक प्रभावित होंगे, जबकि इसके लिए वे सबसे कम जिम्मेदार हैं, इसी परिदृश्य में सूखा और बाढ़







की संख्या भी बढ़ सकती है जिससे संघर्ष की स्थिति भी उपज सकती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जलवायु परिवर्तन पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मानवीय गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक समुद्र का जल स्तर तथा पृथ्वी का औसत तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा। श्री मून के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग पर क्योटो संधि की अवधि खत्म होने से पहले औद्योगिक देशों को वर्ष 2012 तक ग्रीनहाउस गैसों, विशेषकर कार्बन डाइ आक्साइड की मात्रा को अगले दस साल में पांच प्रतिशत के स्तर से नीचे लाना तय हुआ था जिस पर संतोषजनक कार्य नहीं हो सका है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक और हास्यास्पद है कि दुनियाभर में ग्रीनहाउस गैसों का चैथाई हिस्से से अधिक उत्सर्जित करने वाला देश अमेरिका ने अभी तक क्योटो संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

कनाडा स्थित मांट्रियल कॉन्फ़ेरेन्स का विश्वविद्यालय के शोधकर्ता डैमन मैथ्यू का कहना है कि किस देश ने क्लाइमेट चेंज में

सबसे अधिक योगदान किया और वे कौन से देश हैं जो सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने के उपरांत भी इसकी सबसे अधिक कीमत चुका रहे हैं उनके शोध के अनुसार यदि आप आस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे विकसित देश में रहते हैं तो उत्सर्जन को घटाने के लिए धन के तौर पर कार्बन उत्सर्जन का आपका डेबिट क्रमशः 10,000 से 12,000 डॉलर तक बैठता है वहीं अगर आप ब्राजील या भारत जैसे देश से हैं जो आपका क्लाइमेट-क्रेडिट 2000 डॉलर तक बनता है। विश्व के सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन देशों में अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जहां क्रमशः 10825, 7680, 7280, 11,600, 10825, 4240, 10600 डॉलर प्रति व्यक्ति कार्बन डेबिटर हैं जबकि कम कार्बन उत्सर्जक देशों में जिनमें क्रमशः भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, फिलीपींस, नाइजीरिया इत्यादि जैसे कई देश हैं जो क्रमशः 2500, 3280, 2640, 2020, 2640, 2680 डॉलर प्रति व्यक्ति कार्बन डेबिटर हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि विश्व

के संचयी कार्बन ऋण या देनदारियों में अकेले अमेरिका का हिस्सा 40 प्रतिशत बनता है, कनाडा का चार प्रतिशत है जबकि आबादी के हिसाब से जिन देशों में कार्बन उत्सर्जन में कम योगदान रहा है उनमें भारत, चीन, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया जैसे देश हैं जो कुल ब्लड क्रेडिट में 30 प्रतिशत से भी कम भागीदार माने जाते हैं। शोधकर्ता मैथ्यू का मत है कि वैश्विक कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था बनाने में 10 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत होगी जो उस भरपाई के लिए काफी होगा जिन देशों ने इस संदर्भ में अधिक हानि को झेला है। स्पष्ट है कि यूएनओ के हरित जलवायु कोष के लिए प्रस्तावित 10 बिलियन या 100 अरब डॉलर के आंकड़े को मैथ्यू ने बौना सिद्ध किया है। हास्यास्पद और चिंताजनक यह भी है कि अभी तक यूएनओ के इस कोष में विकसित देशों द्वारा केवल 10.2 बिलियन डॉलर ही जमा हो सके हैं आशा की जा रही है वर्ष 2020 तक 10 बिलियन डॉलर की रकम जमा हो सकेगी जो पीड़ित देशों की मदद में काम आ सकती है।

सत्य समाचार फीसर्च

# Public Relations in Banking Sector



Public Relation (PR) is the most important and essential part of the communication. British Institute of Public Relation defined PR as a planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and its public. According to American Institute of PR, Public Relation is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationships between organization and their public. On

the other way, it is an important method for image building, to maintain goodwill and publicity of an organization to win over an extremely competitive market. A favorable image or good reputation helps to increase the sale of a particular company and in case of negative publicity, the company's sale as well as its reputation will be at stake. So, to enhance a company's reputation, several methods are practiced by the PR department to communicate

with the internal and external public. It is a two-way flow of mutual understanding (Sam Black, Practical Public Relations). It is an extended arm and eyes and eard of modern way of management.

The concept of Public Relation dates back to history. In 49 BC reports about the achievements of Julius Caesar was published in a daily, 'Acta Diurna'. In 1066 the Norman conquest of England was depicted in world's first infographic, the Bayeux Tapestry. In



17<sup>th</sup> century the term 'propaganda' was first used by the Catholi Church. In an address to US congress Thomas Jefferson first used the term 'public relation' in 1807. But, the first PR department was established in 1889 by Westinghouse. It was established to fight Thomas electric. This is known as the 'battle of currents'. The term PR was first used in the year-book of railway literature (1897) to communicate between the public and their organization. This is marked as the birth of the Public Relation. The first Public Relations agency, namely 'The Publicity Bureau' was established in 1900.

The first official release was created by Ivy Ledbetter Lee in 1906. It was created on electric train wreck. This was printed in 'The New York Times'. Lee was na American publicity expertand considered as the founder of modern Public Relation and became popular for his work with the Rockefeller family. In 1924 Basil Clark introduces PR in Britain. When wall Street craches in 1929, Public Relatons became a necessity. Edward Louis Barnes was an Austrian-American expert in the field of Public Relatons. He was best known for to encourage female smoking by branding cigarettes with the 'Torches of Freedom'. He was the pioneer in the field of propaganda and worked for leading American corporate

companies like 'Procter and Gamble; 'General Electric; In his obituary (10<sup>th</sup> March, 1995), 'The New York Times referred him as 'The father of Public Relations and leader in opinion making'. Evolution of PR in India was found in our epics Ramayana and M a h a b h a r a t a . T h e administration was very much concerned about their public feelings and opinions. India had master of religious

Government set up different media units to handle Public Relations.

### Role of PR in banking sector

PR is considered as a very crucial and vital part of banking sector for image building, to maintain goodwill and to gain trust of its customers. In case of banking, for their daily transaction customers need interaction with their respective banks. Besides, banks have to



communicators like Gautama Buddha, Shankaracharya. King Ashoka sent his daughter Sanghamitra to Sri Lanka to preach Buddhism. She is known as the first female PR executive in History. Ashokan inscriptions were an indeal example of Public Relations. Systematic practice of PR began with the House of Tata's and by India Railways. After independence, the

inform about their different schemes and facilities to the customers. So, the public relation or customer care department has to play a vital role in entertaining and fulfilling the need of the same. To gain the trust or confidence of its customers, banks need PR support. PR department often do research rgarding customer satisfaction about different

banking schemes and products.

Different methods or tools are used by banks. The traditional methods are by sending News or Press release to different media, Newsletters to the customers and by appearances at public events, such as, trade show, conventions etc. With the advancement of the modern

consent. So, several services are offered to satisfy the need of a customer. Besides, debit and credit cards and net banking is becoming more and more popular now. Phone banking has also made the transactions very. People can access their accounts also through banking apps. Nowadays, it is very easy to get a

an important role to build a positive image about a particular bank; for example, Deepika Padukone is the brand ambassador for Axis Bank from 2014 and Amitabh Bachchan was the brand ambassador for ICICI bank in 2013-14 ICICI bank has also used the Bollywood superstar Shahrukh Khan to boost their overseas business. Bank of Baroda once used leading Indian cricketer Rahul Dravid in 2005. Dravid symbolizes solidity and trust. IndusInd bank preferred actors like Farhan Akhtar, Sharman Joshi and Boman Irani rather than stars. Joshi featured in a service called 'My Account, My Number' to get account numbers as per the choice of the customers. In 2016, Boman Irani and Farhan Akhtar advertise for a new service called 'fingerprint Banking' to allow customers to make transactions on its mobile banking app. Captain of India cricket team, Virat Kohli is associated with the Punjab National Bank since he was 16. Canara bank had chosen the India opener Shikhar Dhawan as their brand ambassador in 2014. Among foreign bank, Royal Bank of Scotland roped in master blaster Sachin Tendulkar in 2008 as their brand ambassador. In 2003 Standard Chartered Bank selected ex-India captain Kapil Dev as a face for their campaign. In 2006 renowned Cricket Sunil Gavasker joined tennis star Sania Mirza as the brand



technology, banking service has now been exposed to our fingertips. PR department can now use internet as a medium of communication. Social media, e-mail, and text messages are used to accomplish their goals.

Banking industry is a service oriented one. Community banks know the importance of public

loan for buying a car or house or to avail a loan for education or to start a new venture. PR in banks works for 24x7 to maintain a good relation with its customers. People can have financial transactions or enquire about a particular service through attractive and useful websites.

Brand ambassadors also play



ambassador of Deutsche Bank.

PR department not only enhances communication and publicity, but also have a pivotal role in crisis management. Routine jobs of PRO do not need a very innovative mind; in fact it is not a very interesting genre. But, in the crisis situations, it is totally different. It is then and only then that the PRO becomes the judge, crisis situation are an acid test for the PRO. The Public Relation is to deal with anything and everything that they have to face in the crisis situations. There is no fixed crisis and therefore there is no particular formula to combat a crisis in a crisis situation. However, there are some basic ways to get going. One must be prepared for the worst and hope for the best. In the crisis situation Public Relations department of an organization has to deal with the major unpredictable event. It is said that when in crises, we must tell the truth and act promptly. The three C's of credibility are to be-compassionate, competent and confident.

For better communication with the public bank have changed a lot. ICICI bank which is the second largest bank of India, Introduced 'Branding' in the Indian banking industry. They first introduced net banking and e-mail marketing. They are the pioneers in retail banking and emphasizes on the data entre availability and data protection solution. For better customer

relation 'MILAP' function is conducted on the third Friday of every month to get feedback from the customers. The outdoor activity also increased from time to time. Besides that they also took several measures to keep in constant touch with their internal public. They also involved themselves in film promotion, as in 'Baghban' (2003)

To launch international credit card, ICICI bank associated

Prerm Ki Deewani Hoon (2003), Veer Zara (2004), Mangal Pandey (2005) Don (2006) etc, at present, IDBI and Exaim bank have temporarily decided not to finance in film industry, but Yes Bank have continued to invest in the same for their profit & publicity. On the other hand State Bank of India one of the leading nationalized banks of India prefers to maintain customer relation by using different media channels to

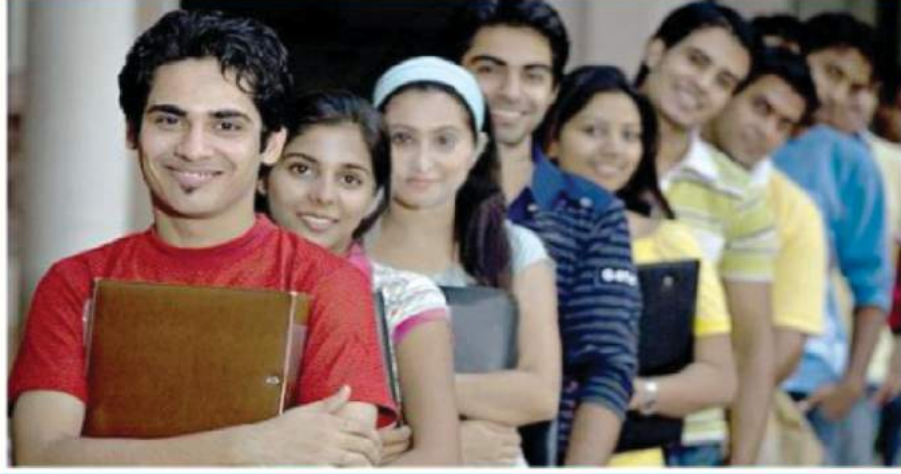


them with Amway India. So, customers can purchase Amway products from Amway distributors to redeem their points. Again, ICICI customers can book railway tickets by using mobile banking system. ICICI Bank also tie-up with the Cartoon Network for their publicity purpose. IDBI and Exim Bank also financed 50% of their budget for film funding. They invested in the films like Aakhen (2002), Qayamt (2003) Main

promote their different services and to gain credibility among its public. In the age of social media and internet technology, Public Relation of banks has now become a very effective and easier way to communicate with their respective customers.

**Ph.D Research Fellow,  
Department of Journalism and Mass  
Communication, University of  
Calcutta.**

# जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल



जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

**: विषय :**

**मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)**

## प्रवेश प्रारंभ

**संपर्क सूत्र**

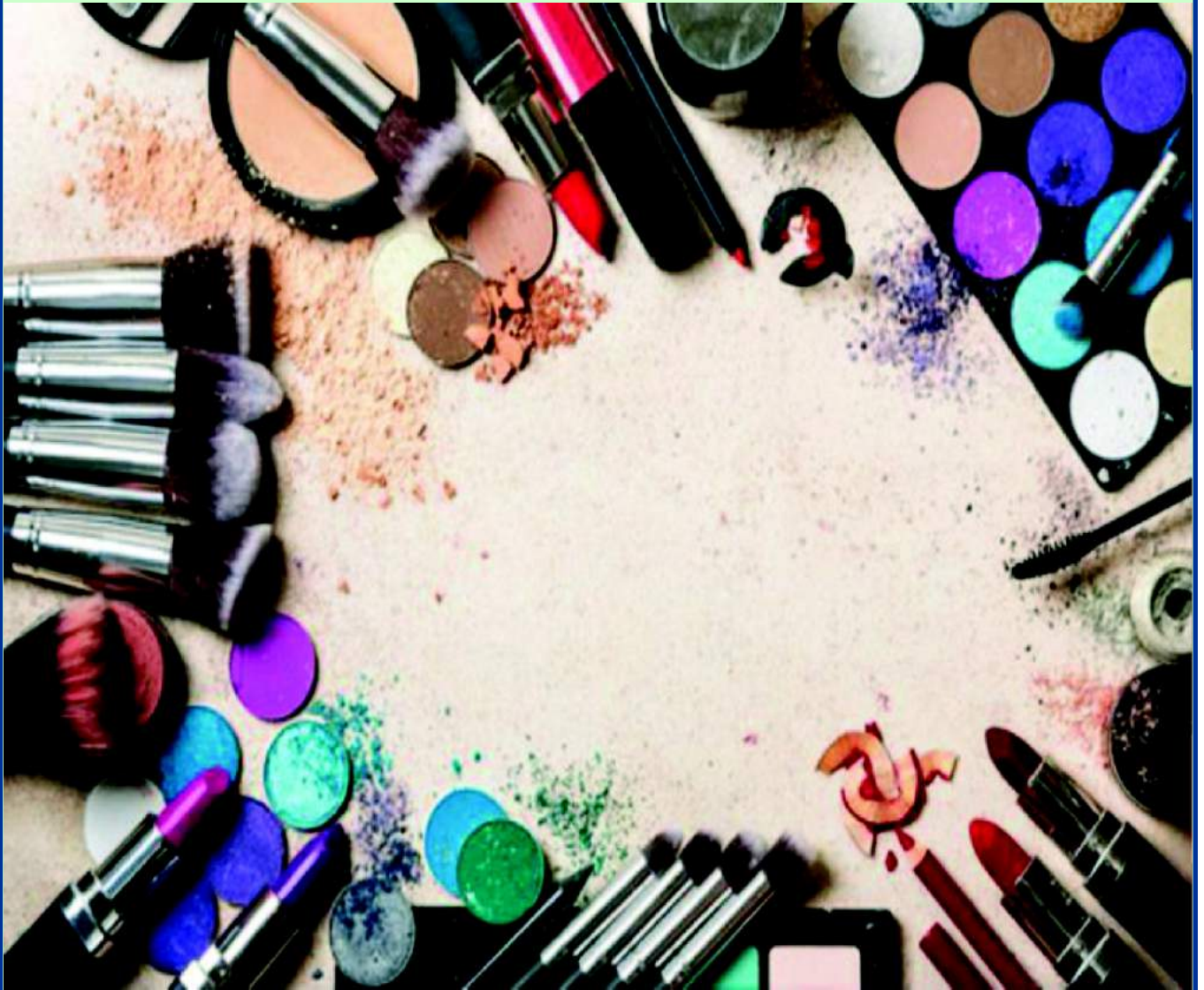
विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.  
संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.



# SAWARNA COSMETICS



**SHOP NO. 101/152, NEW MARKET,  
BHOPAL, M.P. 462016**



सावधानी से गाड़ी चलाएँ  
या आप उसी जगह पहुँच जाएंगे  
जहाँ जाना नहीं चाहते हैं।

निधि ट्रस्ट

जनहित के लिए जारी